Now we will take up the short-duration discussion on the recent steep hike in diesel price and the consequent hardship being faced by the people.

II. Recent steep hike in diesel price and the consequent hardships faced bv people

**श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश)** : उपसभाध्यक्ष महोदया, डीजल के दामों में भारी वृद्धि के सिलसिले में शार्ट डयुरेशन के माध्यम से आपने जो मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मै आभारी हूं। केन्द्र सरकार द्वारा तेरहवी लोक सभा चुनाव के परिणामों का इंतजार किए बगैर आनन-फानन में चुपके से डीजल की कीमत बढाने की जो घोषणा की गई, वह अत्यन्त अनुचित है। एक तरफ जब सारा देश चुनाव के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था तो दूसरी तरफ काम चलाऊ केन्द्रीय सरकार ने इस अलोकप्रिय निर्णय की घोषणा की। इस निर्णय को लेते वक्त आने वाली सरकार का भी इंतजार नही किया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि इनकी जनतांत्रिक प्रकिया में कोई आस्था नही है, जो आने वाली सरकार का इंतजार भी नही कर सकते थे।

महोदया, यह जो निर्णय है, जो डीजल के दामों में भारी वृद्धि की गई लगभग 35 प्रतिशत की, उसकी वजह से आम जनता पर निरंतर गाज गिर रही है। आम आदमी की उपभोक्ता चीजों की उपलब्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आम आदमी के उपयोग में आने वाली जो चीजें है उनकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और बाजार में आपूर्ति की कमी की वजह से बिचौलियों और दलालों की बन आई है। कई समाचार पत्रों ने तो यहां तक लिखा है कि बिचौलिए और दलाल वे लोग है, जिनसे इस सरकार के बैठे हुए लोगों ने चुनाव के समय चंदे की वसूली की थी। यह जो निर्णय है वह किसानों के हितों के बिल्कुल विपरीत है।

महोदया, यह जो सामान्य उपभोक्ता की चीजें है, इनके मूल्यों में वृद्धि के सिलसिले में वर्तमान प्रधान मंत्री ने भी समय-समय पर अपने भाषण में कहा है कि आनन फानन में, बगैर प्रतिपक्ष को विश्र्वास में लिए इस प्रकार की चीजों में कीमतों की वृद्धि नही की जानी चाहिए। मै तिथि का उल्लेख करना चाहूंगा, जुलाई 1996 में स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह मत था कि जो सामान्य आदमी के उपभोग में आने वाली चीजें है उनके मूल्यों में वृद्धि इस तरीके से नही की जानी चाहिए कि आम आदमी की कमर टूट जाए, आम आदमी परेशान हो जाए या कीमतों की बेतहाशा वृद्धि की वजह से आम आदमी यह महसूस करने लगे कि उसका जीवन- यापन बहुत दूभर हो गया है।

महोदया, देश में पहले कभी ऐसी कोई भी सरकार नही बनी, जिसने डीजल की कीमत इस प्रकार अनाप-शनाप ढ़ंग से 35 प्रतिशत बढा दी हो। महोदया, जहां रेलवे ट्रेक नही है, जो पहाड़ी इलाके है, जहां प्राइवेट ट्रांसपोर्टस के जरिए लोग अपना सामान भेजते है, इस डीजल की कीमत की वृद्धि की वजह से वह सारे इलाके भी प्रभावित होंगे और वह लोग भी प्रभावित होंगे, जो इस प्रकार ट्रांसपोर्टर्स के जरिए अपना सामान भेजते है। इसलिए महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि की वजह से आम आदमी बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है, जो आम आदमी के उपयोग में आने वाली चीजें है उनकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वह कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहा है, लिहाजा यह सरकार अपना अड़ियलपन अलग करके, जिद्दी रवैया अख्तियार न करते हुए, जो डीजल की कीमतें बढाने का निर्णय है, उसके बारे में पुनः विचार करे और इस वृद्धि को कम करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री राघवजी (मध्य प्रदेश)** : उपसभाध्यक्ष महोदया, डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है और उससे जन-जीवन प्रभावित हुआ है, इसमें कोई दो मत नही है लेकिन डीजल के दामों में पहली बार वृद्धि हुई है, ऐसी बात नही है। मुझे याद है, जब 1967 में हम चुनाव लड़ते थे तो उस वक्त एक रुपया गैलन डीजल मिलता था, यानी लगभग 20 पैसे लीटर और आज उसी डीजल का दाम 15 रुपए हो गया है और ये कीमतें एक दिन में नही बढी है, ये कीमतें धीरे-धीरे बढी है। कीमतें केवल डीजल में ही नही बढ़ी है और चीजों की कीमतें भी बढी है। लेकिन यह बात सही है कि जो यह दाम बढे है इनसे जन-जीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन ये बेतहाशा है, इस बात से शायद मै सहमत नही हूं। इसलिए नही हूं कि अभी जो थोक मूल्य सूचकांक प्रकाशित हुए है डीजल के दाम बढने से, उनमें दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह ठीक से रिकार्ड किया हुआ दाम प्रकाशित हुआ है और इसलिए उसको अतिश्योक्ति के रुप में बताना मेरे ख्याल से ठीक नही होगा। लेकिन ये दाम क्यों बढे और ये दाम क्या इसी सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है? 1 सितम्बर, 1997 को केबिनेट की मीटिग हुई थी, उस समय यह सरकार नही थी, और केबिनेट की उस मीटिग में यह निर्णय किया गया था कि भविष्य में डीजल आदि पर जो सब्सिडी दी जाती है, उसके स्थान पर अभी वर्तमान में नियंत्रित कीमत पद्धति है, उसको बदलकर और आयात के जो दाम होते है, उसके आधार पर कीमतें तय हों, एक बात और दूसरी बात यह भी तय की गई उस वक्त की ऑयल पूल एकाउंट में घाटा नही होना चाहिए। उस निर्णय से कीमते बढना बिल्कुल स्वाभाविक था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें बढी है, वे फरवरी, 1997 से तो एकदम बढना शुरु हो गई। फरवरी, 1997 में जो 3200 रुपय मीट्रिक टन डीजल की आयातित कीमत थी, वह बढकर 7000 रुपए मीट्रिक टन हो गई, यानी दुगुने से भी ज्यादा वृद्धि हुई, 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्योकि चुनाव थे और चूंकि उसके पहले अविश्वास प्रस्ताव वाजपेजी सरकार के खिलाफ पास हो चुका था, केयर टेकर गवर्नमेंट थी और इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट कीमतें बढाने का निर्णय उस वक्त नही ले सकती थी। नई सरकार के निर्णय तक उसको इंतजार करना आवश्यक था और इसलिए उसका इंतजार किया गया। लेकिन यह 120 प्रतिशत की वृद्धि जो आयातित डीजल की कीमतों में हुई है और जिस वृद्धि करने के बारे में निर्णय 1 सितम्बर, 1997 को लिया जा चुका था कि डीजल में कीमतें इस आधार पर निर्धारित नही की जाएंगी की सब्सिडी मिलती रहेगी, बल्कि आयात का जो मूल्य होगा, इस आधार पर निर्धारित की जाएंगी, तो इस निर्णय को आज प्रभावी करना जरुरी था और अन्य कारणों से भी वह जरुरी था। अगर वह नही किया जाता तो ऑयल पूल का घाटा,जो आज लगभग 5000 करोड़ रुपए का है, इस वर्ष के अंत आते-आते तक वह 10,000 करोड़ रुपए का हो जाता। जिस वक्त यह निर्णय हुआ था, 1 सितम्बर, 1997 को, उस वक्त से ही कुछ वस्तुओं के दाम तो बाजार भाव के आधार पर तय हो चुके थे, उनमें बिटूमिन शामिल है, फरनिश ऑयल शामिल है। ऐसी कुछ वस्तुएं है जिनके दाम आज बिल्कुल बाजार भाव से चल रहे है, लेकिन डीजल एल.पी.जी. और कैरोसीन, इनमें सब्सिडी बराबर चलती रही, इसलिए कि नई सरकार के गठन के बाद इस पर निर्णय हो सकता था अभी केवल डीजल के दामों में ही वृद्धि है। महोदया, अभी केरोसिन में साढ़े रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आर्थिक सहायता अकेले केरोसिन में देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से एल.पी.जी. में जो सहायता दी जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि के बावजूद भी उस हिसाब से एल.पी.जी. की कीमतें नही बढ़ी है। इसके कारण इस वर्ष के अंत तक 5,400 करोड़ रुपए की सहायता एल.पी.जी. के एकाउंट

में देनी पड़ेगी। इस प्रकार इतनी आर्थिक सहायता इन दो वस्तुओं में हमें देनी पड़ रही है। अगर डीजल में भी हमें आर्थिक सहायता देनी पड़ती तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ जाता।

महोदया, आज भी हमें क्रूड ऑयल का आधे से अधिक हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है क्योकि हमारी जितनी आवश्यकता है, हमारे यहां उसका केवल एक-तिहाई उत्पादन होता है और दो-तिहाई हिस्से के लिए हमें आयात पर निर्भर करना पड़ता है। अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो कीमतें बढना लाजिमी है लेकिन फिर भी कीमतें उस अनुपात में नही बढ़ी है जिस अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी है। मैंने आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 120 प्रतिशत बढ़ी है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) पीठासीन हुए**

महोदय, हमारे यहां दामों में केवल 35 से 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है लेकिन मै यह कहना चाहता हूं कि यहां पर इसका नाजायज दुरुपयोग भी हो रहा है। उदाहरण के लिए डीजल के दाम बढ़े केवल 35 प्रतिशत या 40 प्रतिशत लेकिन दिल्ली सरकार ने बस का किराया कितना बढ़ा दिया? लगभग दुगुना कर दिया। जब कि बस के किराए में डीजल का जो भाग रहता है वह पूरा का पूरा डीजल की वजह से नही है। खर्च में उसका भाग एक-तिहाई रहता है और अगर यहां पर 35 परासेंट दाम बढ गए है तो 11 परसेंट बस का किराया बढ़ाना चाहिए था लेकिन दुगुना कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी चूकि राष्ट्रीयकृत बसें अधिक है इसलिए वहां पर भी बसों का किराया 33 परसेंट बढ़ा दिया गया है जब कि 11 परसेंट बढना चाहिए था। अगर डीजल की कीमतें बढने के कारण यह वृद्धि कर रहे है तो 11 परसेंट बढ़ाना चाहिए था।

महोदय, केन्द्रीय सरकार द्वारा डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, इसकी आड़ लेकर यह ढ़िढ़ोरा पीटा जा रहा है। सभी जानते है कि दिल्ली में किसकी सरकार है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है। क्या ऐसा करना आवश्यक था, यह बात समझने की आवश्यकता है। अभी डीजल के दाम जो बढ़े है वह तो ठीक है लेकिन अब ऐसे कुछ उपाय करने चाहिए कि जिससे आगे चलकर कुछ राहत- मिल सके। कुछ ऐसे दूरगामी उपाय किए जा सकते है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटाने और बढने से हमारा बाजार प्रभावित न हो। जब डीजल के दाम बढते है तो हमारा बाजार प्रभावित न हो। जब डीजल के दाम बढते है तो हमारा बाजार प्रभावित होता है। जब डीजल के दाम बढते है तो किसान प्रभावित होता है। जब डीजल के दाम बढते है तो उपभोक्ता प्रभावित होता है। इसके लिए सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए।

महोदय, हमारे यहां एक समस्या तो यह है कि हमारा घरेलू उत्पादन घट रहा है। हमारा क्रूड ऑयल का घरेलू उत्पादन 1993-94 में 330 लाख टन था लेकिन ऐसी आशंका है कि 1999-2000 में यह घटकर 325 लाख टन रह जाएगा। यानी बढने के बजाय 5 लाख टन यह घटने वाला है। हमारा क्रूड ऑयाल का आयात 1990-91 में 207 लाख टन था जो कि 1999-2000 में 545 लाख टन होने वाला है। आयात में तो हम ढाई गुना आगे बढ गए लेकिन उत्पादन में हम वही के वही रह गए है बल्कि थोड़ा पीछे जा रहे है। तो आज इस बात की आवश्यकताअ है कि हम अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाएं। इस देश में जो उत्पादन क्रूड ऑयल का होता है, उसको बढ़ाने के बारे में हमें विचार करना चाहिए। यह घट क्यों रहा है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए और उन कारणों को दूर करने के उपायों पर भी विचार करना चाहिए ताकि हमको विदेशों से आयात किए जाने वाले क्रूड ऑयल पर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े। इसके

साथ-साथ मै यह भी कहना चाहता हूं कि केरोसिन का दाम जो फेयर प्राईस शॉप्स पर फिक्स है, उसके हिसाब से 2,80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से केरोसिन मिलना चाहिए लेकिन किसी भी तो उपभोक्ता को वह 5 रुपए प्रति लीटर या 7 रुपए प्रति लीटर से कम में मिलता नही है। चाहे गरीब किसान पहुंच जाए चाहे गरीब आदिवासी पहुंच जाए किसी भी राज्य में नही मिलता। मै एक राज्य की बात नही करता हूं। तो क्या वास्तव में उसको इसी रेट पर रखने की आवश्यकता है? इसके पीछे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार का पैसा कहां पहुंच रहा है, किसके पास जा रहा है? क्या यह पैसा भ्रष्टाचार पर देने की आवश्यकता है? आर्थिक सहायता के नाम पर इस प्रकार का गोरख धंधा चल रहा है। यह कब तक चलना चाहिए इस पर विचार होना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि अधिकांश केरोसिन मिलावट में जा रहा है, उपभोक्ताओं के पास कम जा रहा है और अगर उपभोक्ताओं के पास जा रहा है तो घोषित दामों पर नही जा रहा है। इसलिए इस स्थिति पर पुनर्विचार होना चाहिए। केरोसिन पर आज पांच-साढ़े पांच रुपए प्रति लीटर की जो आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है उसको इतना देने की आवश्यकता क्या रह गई और इसीलिए केरोसिन के दामों पर पुनर्विचार होना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। एक तो ऑयल पूल का घाटा कम होगा और दूसरा लाभ यह होगा कि मिलावट नही होगी। आज ट्रेक्टर में जब मिलावटी डीजल मिलता है तो उतना नुकसान उसको कीमत बढने से नही होता होगा जितना उसको मिलावटी डीजल खरीदने से होता है। आज पैट्रोल के दामों से किसी को इतनी परेशानी शायद नही होगी लेकिन पेट्रोल में मिलावट होने से उसकी गाड़ी इत्यादि को नुकसान पहुंचता है वह इससे कष्टदायक होता है। भी रुकेगी। अतः केरोसिन के दामों के बारे में पुनर्विचार होना चाहिए। एल.पी.जी. के बारे में भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज हम देख रहे कि बाजार में प्राइवेट निजी कम्पनियों के माध्यम से जो सरकारी कीमत है उससे कोई 20 प्रतिशत ऊपर कीमत पर खुले बाजार में एल.पी.जी. उपलब्ध है। लेकिन सरकारी घाटा काफी ज्यादा होता है। जो आर्थिक सहायता दे रहे है वह जोड़ करके रखा जाए तो निजी कम्पनी से जो एल.पी.जी. मिल रही है उससे ज्यादा दाम हो जाएगा। इसलिए एल.पी.जी. के बारे में भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यदि उपयुक्त हो सके तो यह काम प्राइवेट कम्पनियों के जिम्मे छोड़ देना चाहिए।

**श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल)** : सरकार को भी निजी करदो।

**श्री राघवजी** : अगर दस-पन्द्रह रुपए बढने से एल.पी.जी. आसानी से उपलब्ध हो सकती है तथा उसमें होने वाला भ्रष्टाचार रुक सकता है, सेवाएं ज्यादा अच्छी मिल सकती है तो प्रतिस्पर्धा के रुप से एल.पी.जी. उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सरकार भी इस प्रतिस्पर्धा में आना चाहे तो आए लेकिन यह जो भ्रष्टाचार इसके अंतर्गत होता है तथा इसकी कीमत बढ जाती है सरकारी एजेंसी बंटने के कारण, तो उससे जो अर्थतंत्र की व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है यह कम से कम रुक जाएगा।

फिर डीजल की खपत कैसे कम हो इन बातों पर विचार होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है। लेकिन कुछ बदलाव ऐसा भी आया है जो लाभकारी नही है। आज इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वह ट्रेक्टर खरीदे। जब वह ट्रेक्टर खरीदता है तो किसी रुप में वह लाभदायक नही होता। उसने बैल हटा दिए, ट्रेक्टर पर लगने वाली लागत का ब्याज, उसकी घिसावट, उसमें डीजल का खर्च यह सब मिलाने के बाद जब हिसाब लगाया जाता है तो यह खेती किसी प्रकार से लाभदायक नही हो पाती। तो क्या इस प्रकार की

आवश्यकता है कि 10 एकड़ जमीन वाला किसान भी ट्रेक्टर से खेती करे? वह बैल से खेती कर सकता है और अगर बैल से खेती करनी है तो पशु रक्षण पर भी जोर देना पड़ेगा। फिर इस बात की आवश्यकता पैदा होगी कि जो पशु मांस निर्यात किया जाता है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उससे बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा नही मिल रही है। तीन सौ करोड़ की विदेशी मुद्रा की आड़ में कितने ही उपयोगी पशु काटे जा रहे है। आज बैलों का अभाव हो रहा है, आज उन जानवरों का अभाव हो रहा है जो गाड़ियां खीच सकते है, जो खेती कर सकते है और अगर उनका उपयोग छोटे-छोटे खेतों में जैसे पहले होता था आगे भी किया जाए तो इसमें डीजल की बहुत बचत हो सकती है और खेती भी लाभदायक हो सकती है। दस एकड़ जमीन वाला जो किसान ट्रेक्टर खरीदता है उसका ट्रेक्टर आगे जाकर बिक जाता है तथा किश्तों का भुगतान भी नही कर पाता है और इस प्रकार वह बरबाद हो जाता है। इससे उसकी बरबादी भी रुक सकती है। ऐसी स्थिति में कम से कम डीजल का व्यय किस प्रकार से बचाया जा सके, इसकी खपत कैसे कम की जा सके इसके बारे में विचार होना चाहिए। अभी यह व्यवस्था भी कई जगह चल रही है कि एल.पी.जी. से वाहन चलाए जाएं। यहां की ऑयल कंपनियां भी इस बात का इंतजार कर रही है कि यह छूट उनको मिल जाए तो वे एल.पी.जी. की व्यवस्था वाले वाहन देने की व्यवस्था करेंगी क्योकि यह आयात किया जा सकता है। एल.पी.जी. से वाहन चलेंगे तो प्रदूषण कम होगा और डीजल या दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्टस की खपत भी कम होगी। तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय, इसके साथ ही रेल यातायात और जल यातायात को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आज जब रेल यातायात में डीजल खर्च का इतना अंश है, ऐसा हिसाब लगाया जाता है तो रेल यातायात में यह केवल आठ प्रतिशत है जबकि ट्रक के माध्यम से जो माल ढोया जाता है, उसमें डीजल का जो कंपोनेंट होता है, वह लगभग सत्तर प्रतिशत होता है। रेल यातायात सस्ता पड़ता है, ट्रक यातायात महंगा पड़ता है लेकिन ट्रक यातायात की लॉबी कुछ ऐसी जबरदस्त रही है पिछले दिनों कि रेल यातायात के हिस्से में जो ढुलाई जानी चाहिए थी, वह ट्रक यातायात वाले अपनी ढुलाई में ले गए। कई वर्षो से रेल में पीसमीन बैगन मिलना बंद हो गया है। अगर पूरा रेक लेना हो तो लीजिए वरना अगर एक वैगन चाहिए माल बाहर भेजने के लिए तो वह आपको उपलब्ध नही होगा। आखिर क्यो? इसलिए डीजल का ऑयल पूल का सारा हिसाब लगाने के बाद आयात का जो बोझ हमारे ऊपर पड़ रहा है, इस सबको देखने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि रेल यातायात को बढ़ावा दिया जाए

महोदय, इससे भी ज्यादा लाभकारी है वाटर ट्रांसपोर्ट। जल यातायात रेल यातायात से भी सस्ता पड़ता है। हमारे यहां समुद्र का काफी बड़ा किनार है जहां पर जल यातायात का उपयोग हो सकता है। मुम्बई से लेकर मद्रास तक और मद्रास से लेकर कलकत्ता तक पूरा क्षेत्र जो है, जल यातायात में उसका उपयोग हो सकता है। इसके लिए हिदुस्तान में ऐसी भी अनेक नदियां है जो बारहों महीने जल यातायात के लिए उपयुक्त है। वहां पर जल यातायात का उपयोग किया जा सकता है और ऐसा करने से डीजल की बचत तो होगी ही, यातायात के दाम भी सस्ते होंगे। यातायात का सबसे सस्ता साधन यदि कोई है तो वह जल यातायात ही है इसलिए इसको बढ़ावा मिलना चाहिए।

महोदय, किसानों को डीजल की दाम वृद्धि होने से बहुत क्षति हुई है या होने की अपेक्षा है, क्योकि किसान इसलिए भी दुखी होता है कि जब उसकी फसल आती है तो उसे कोई परवाह नही होती डीजल

के दामों की। वह चाहे 15 रुपए लीटर हो या 16 रुपए लीटर हो लेकिन हिदुस्तान में कृषि मानसून पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है। इसलिए यदि प्रकृति अनुकुल नहीं हुई मान्सून अनुकूल नहीं हुआ तो फिर खेती लाभकारी नहीं रह पाती। कई बार पूरी की पूरी खेती नष्ट हो जाती है, कभी पूरी नहीं तो आधी खेती नष्ट हो जाती है और उसको जितना उत्पादन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलने के कारण उसकी खेती घाटे का सौदा बन जाती है। ऐसे वक्त में डीजल की बढ़ी हुई कीमतें उसको अखरती है और प्रायः देखने में यह आता है कि तीन-चार वर्ष में एक वर्ष औसा आता है जो किसान के लिए दुखदायी होता है। उस समय उसकी फसल बरबाद होती है और दो-तीन साल में जो उसने कमाया होता है, वह उस एक साल में बरबाद हो जाता है।

महोदय, अभी बाढ और साइक्लोन की चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में भी कुछ जिलों में, सात-आठ जिलों में अतिवृष्टि के कारण, बाढ के कारण इतना नुकसान हुआ कि सोयाबीन का जो मध्य प्रदेश में अस्सी प्रतिशत उत्पादन होता है, वह उसी क्षेत्र में होता है जहां पर अतिवृष्टि हुई है, वह पूरा का पूरा साफ हो गया। एक-एक जिले में पच्चीस करोड़ के सोयाबीन का नुकसान हुआ। हजारों घर गिर गए, पशु मर गए। यह सब नुकसान जब किसान को होता है तब उसकी आत्मा बहुत दुखी होती है। उसका परिवार बरबाद हो जाता है। ऐसे वक्त में उसको मदद मिलनी चाहिए जब इस प्रकार उसकी फसल खराब होती है, चाहे वह बाढ के कारण हो चाहे साइक्लोन के कारण हो चाहे अतिवृष्टि के कारण हो चाहे सूखे के कारण हो। इससे फसल को नुकसान होता है और किसान की बर्बादी होती है। ऐसे वक्त पर अगर किसान की सहायता की जाए चाहे बीमे से की जाए या, जो नई योजना आ रही है उससे हो या अन्य किसी माध्यम से तो मैं समझता हूं कि जो परेशानी किसान को उठानी पड़ रही है यह नहीं उठानी पड़ेगी। जो अस्सी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है उसको जरा सी भी यदि राहत मिल सकेगी तो डीजल के दामों मे जो वृद्धि हुई है वह उसके लिए दुखदाई नहीं होगा। ऐसी मेरी मान्यता है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि नई फसल बीमा योजना जितनी जल्दी हो सके लागू की जाए। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो किसान को क्षति होती है उसकी पूर्ति के लिए किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने साईक्लोन, प्राकृतिक आपदाओं पर अपनी बात यहां रखी है करीब-करीब सभी ने एक ही बात कही है कि केन्द्र सरकार को पर्याप्त मदद करनी चाहिए। केन्द्र सरकार मदद कहां से करेगी। राज्य सरकार तो मदद नहीं कर पा रही हैं, यह बात ठीक है। क्योंकि आजकल उनके पास केवल इतनी ही आय होती है कि वे केवल वेतन ही दे पाती हैं। इससे आगे वे नहीं बढ पा रही हैं। सारे विकास कार्य ठप्प हैं लेकिन केन्द्र सरकार से अपेक्षा है। अगर हमारे मित्रगण केन्द्र सरकार के ऊपर यह प्रतिबंध लगाएं कि डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो बढ़े लेकिन आप अपने बाजार में मत बढ़ाओ तो जिन राज्यों में चक्रवात आ रहे हैं, बाढ आ रही हैं उनकी मदद कैसे होगी? अभी प्रधान मंत्री जी ने ढाई करोड़ का एक पैकेज उनकी सहायता के लिए घोषित किया है। कश्मीर के लिए पहले ही घोषित हो चुका है। इसी तरह से जिन राज्य सरकारों को पैकेज की आवश्यकता है तो वह कैसे घोषित होगी? अगर हम सब्सिडीज चलाते रहेंगे और सब्सिडीज में लम्बे-चौड़े घाटे की पूर्ति करने की बात नहीं सोचेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए केन्द्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में केवल चालीस प्रतिशत बढ़े हैं। यह बढ़ोत्तरी बिल्कुल सही है इसे गलत नहीं कहा जा सकता। यह न्यायपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है। मेरा पूरा विश्वास है अगर माननीय मनमोहन सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, यदि वे सरकार में

मंत्री या वित्त मंत्री होते तो उनसे परामर्श लिया जाता तो क्या वे सरकार को परामर्श नहीं देते कि डीजल के दाम बढ़ाए जाएं? मैं समझता हूं कि उनका यही मत होता कि डीजल के दाम बढ़ाए जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Hon'ble Members, please, please. Several Members have requested that they have to catch their flight, therefore, they should be permitted to speak. Though we are not cutting short the time, the only thing I would request is that there should not be a repetition of the same thing. Shri Margabandu, please.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): The entire nation is very much concerned over the 35% price hike in the price of diesel and hundred per cent of the crude oil. The sorry state of affairs in this case is that a decision was taken in the year 1998 that the price of diesel and other things would be reduced. But within 9 months, the prices have shot up like anything. It is unfortunate that the present BJP Government did not take that decision while it was in power, but, when they were acting as a caretaker Government, on 5.10.1999, when the counting of votes was to begin the next day, the decision to increase the diesel price by 35% was taken by the

erstwhile Petroleum Minister. The present Petroleum Minister has given a letter which justifies the increase. He says, "I have prepared the enclosed short note on recent diesel price hike. I do hope that you will kindly find it informative and useful". This is the information given. Why has the price been increased? What is the alternative suggestion given by the Central Government? What is the Central Government doing to reduce the diesel price to solve the problems of the common man? But no suggestion has been put forward.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): I want suggestions from you.

SHRI R. MARGABANDU: I will give my suggestions. But the Minister has not mentioned anything as to what he is going to do. Everybody is concerned about the hike in prices. Lorry owners have been on strike for more than a week causing a loss of Rs. 800 crores every day. Even the bus owners have announced that they would resort to strike. In such a situation, what is the Government going to do? The hon. Minister wants to have my suggestions. My suggestion is, they can increase the tax on luxury items like cars and other things. Whoever is using luxury items can be taxed. In this way you can reduce the diesel price and customs duty also.

In Tamil Nadu, all the political parties have joined hands and they have announced that they would hold a Hartal on 4th November, 1999. The AIADMK in its Executive Committee meeting pleaded before the Central Government to roll back this price hike. But nothing has been done so far.

The Prime Minister said, "There is no question of roll-back of diesel prices". Is this the stand of the Government? The whole nation is concerned about the hike in diesel prices. They must come forward with some solution to solve this problem. They are simply saying that they cannot do anything in this matter. If this is the stand of the Government then how will they give good governance to the people? What steps are they going to take in this regard?

So far as Tamil Nadu is concerned, the bus fare has already been hiked by 40 to 60 per cent. The Chief Minister says............*(Interruptions).*

SHRI S. VIDHUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, he is giving wrong information. He is misleading the House.

THE VICE-CHAIMAN (SHRI SANATAN BISI): Please listen to him. You will get a chance to speak. Mr. Margabandu, please conclude.

SHRI R. MARGABANDU: Sir, I did not say anything at all. Is this the attitude of the DMK party? I am not able to understand this. The present Chief Minister earlier said that the bus fare would not be hiked before the year 2001. But now they have hiked the bus fare on the ground that the diesel price has been increased. They have also increased the price of paddy. The price of cement also has been increased. In Andhra Pradesh, one bag of cement is sold at Rs. 120/-. Iq Gujarat its price is Rs. 95*- per bag. In Delhi the price of cement is Rs. 13C- per bag. But in Tamil Nadu the price of cement has been raised from Rs. 110/- to Rs. 200/- per bag. What is the reason? When there is no change in electricity charges and when all the other materials which are required for the production of cement are available, then why have they increased the price from Rs. 110/- to Rs. 20Q/-? Is it not a fact that some vested interests, a person who is in power, has purchased a cement factory in Tamil Nadu? Therefore, I would request the Government to take all these things into consideration and see to it that the price of diesel is rolled back to solve the problem of the common man. Thank you.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, I want to make a submission. The hon. Member has made a sweeping charge against the State Government. After all, they cannot defend themselves here....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I will give a chance to that party, and at that time, they can respond....*(Interruptions).* Mr. Margabandu, please take your seat...*(Interruptions).*

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the name 'Tamil Nadu' may be deleted ......*(Interruptions).*

SHRI R. MARGABANDU: The Government has taken an umbrage under this .....*(Interruptions).*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: When my turn comes, I will respond to this.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It is not fair to make a charge against a State Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Now, Shri Rama Shankar Kaushik.

**श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश)**: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, डीजल के दामों में जो भारी वृद्धि हुई है, इस समस्या को लेकर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, यह समस्या न केवल 76 फीसदी जो हमारे किसान हैं उनकी समस्या है, बल्कि यह पूरे देश के सभी उपभोक्ताओं की समस्या है, क्योकि डीजल एक ऊर्जा है और ऊर्जा के दामों में जब भी वृद्धि होती है तो उसका असर हर चीज पर पड़ता है। किसान इससे बहुत परेशान हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी जगहों पर जहां पर पानी देकर गेहूं बोया जाता है इसको कारण बुआई नही हुई है। इससे रबी की फसल को बहुत नुकसान होने की संभावना है। श्रीमन, एक साथ इतनी वृद्धि आज तक किसी सरकार ने कभी नही की है जितनी कि इस सरकार ने, जो अपने को किसानों का मसीहा, किसानों का हमदर्द कहने का दावा करती है जितनी वृद्धि उसने की है उतनी वृद्धि किसी सरकार ने नही की और मजे की बात श्रीमन यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल के दाम घटते है तब हमारे यहां कम पैसा घटाया जाता है। जितना घटाना चाहिए उतना नही घटाते है। 1998-99 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें काफी कम हुई लेकिन हमारे यहां केवल एक रुपया घटाया गया। बढ़ी हुई कीमतों की तुलना में उनके अनुपात में इसे कम से कम तीन रुपया घटाया चाहिए था। 1998-99 की मै बात कर रहा हूं। 1998-99 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो दामों में कमी आई थी उस समय हमारी इस सरकार ने केवल एक रुपया की घटौती इसमें की थी और वह भी जब 1999-2000 का बजट रखा गया तो उसमें एक पैसा सेस लगाकर वह एक रुपये की जो कटौती की थी उसको भी खत्म कर दिया। श्रीमन, सवाल इस चीज का पैदा होता है, यह कहते है कि जो पहली सरकार थी, राष्ट्रीय लोकतंत्र मोर्चे की सरकार उसने यह फैसला लिया था। लेकिन यहां पर यह सवाल नही है कि फैसला किसने किया। फैसला किसी ने भी लिया हो लेकिन उन्होने उस पर अमल नही किया था और यह बात भी सही है कि उस समय जो फैसला किया था वह केवल 15 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसका विरोध बी.जे.पी. ने पूरा जमकर किया था और वह लागू नही हुआ था। यह बात सही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमतों वृद्धि हुई है और हमारे यहां भी इसमें वृद्धि होनी चाहिए, यह मै मानता हूं लेकिन यहां पर इस बात को देखा जाए कि क्या 1997 के निर्णय के अनुरुप यह वृद्धि हुई है? महोदय, नौ बार डीजल के मूल्यों में कटौती या बढ़ोत्तरी हुई है। श्रीमन, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए है उनको ही आप देखें तो किसी में इतनी बढ़ोत्तरी हुई है। श्रीमन, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए है उनको ही आप देखें तो किसी में न इतनी बढ़ोत्तरी है और न इतनी घटोत्तरी है। जो फिगर इन्होने यहां पर दी है, मै आपको बता देता हूं। एक बार 10.34 पैसे, एक बार 10.29 पैसे मै अलग-अलग बता रहा हूं फिर 10.39 पैसे, 10.25 पैसे 10.01 पैसे, 8.87 पैसे, 8.89 पैसे, 9.94 पैसे, 10.37 पैसे, 13.91 पैसे ये अब बढ़े है। यानी 40 फीसदी की बढ़ोत्तरी इसमें की गई है। तो श्रीमन, अगर इनको किसानों का भला करना ही था और किसानों की बात जैसे अभी माननीय साथी कह रहे थे यह भी एक मजेदार बात है कि यह जो डयूटी लगती है इस पर कितनी डयूटी लगती है इस पर कितनी डयूटी लगी इसी छमाही में, जो इस साल चल रहा था, बजट सत्र, इसी छमाही में 600 करोड़ रुपया राजस्व का फायदा यह

सरकार उठाएगी। डीजल के ऊपर जो डयूटी लगाई गई है, उससे 600 करोड़ रुपये का मुनाफा ही होगा इनका राजस्व बढ़ेगा अर्थात जनता के घर में आग लगे यह उससे तापें। उनको तो मूल्य ज्यादा देना पड़ेगा और इनका राजस्व बढ़ेगा। अगर इन्हें किसानों के प्रति हमदर्दी है तो मेरा निवेदन है कि यह 600 करोड़ रुपया समायोजित करें जो इन्होने वृद्धि की है। जहां तक तेल पूल के घाटे का सवाल है, यह भी एक मजेदार किस्सा है, मजेदार बातें है। यह बताते है कि 5000 करोड़ रुपये का घाटा हम को हो रहा है हालांकि दस हजार करोड़ का यह अनुमान लगाते है अगर यह वृद्धि नही करते। मै यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले 18200 करोड़ रुपये का घाटा भी हो चुका है। वह भी सरकार ने सहा है लेकिन 5000

करोड़ रुपये के घाटे में एक हजार करोड़ का विविध खर्च भी शामिल है जिसका का कोई हिसाब नही है। 5000 करोड़ रुपये का जो घाटा दिखाया गया है उसमें एक हजार करोड़ रुपया ऐसे खर्च में दिखाया गया है जिसको कोई साफ बताया नही जाता कि किस मद में खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। यह एक बड़ा भारी सवाल है। (व्यवधान) मै यह कह रहा था कि यह जो डयूटी 30 प्रतिशत की लगाते है, यह भी अधिकतम कस्टम डयूटी है जो सब उपभोक्ताओं को सहनी पड़ती है, किसानों को सहनी पड़ती है। 600 करोड़ रुपये का जी मुनाफा राजस्व में हो रहा है कीमत बढने के कारण उसका समायोजन किसान के हित में कर दें। इतना ही करें। मै एक बात और कहना चाहता हूं मै ज्यादा टाइम नही लूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)** : आपका टाइम हो गया। आपके पांच मिनट थे, आपने सात मिनट ले लिये है।

**श्री राम शंकर कौशिक** : थोड़ा बहुत समय आप सब को देते है, मुझे भी दे दीजिये। दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने हमारी विभिन्न तेल कम्पनियों को पांच और सात साल के लिए तेल बांड जारी किये है लेकिन दो साल के अन्दर ही उनको रिडीम कर दिया। अगर इनका भी हिसाब लगाया जाए तो तेल पूल खाते में 5000 करोड़ रुपये का घाटा नही है इनको पूल में तो बढ़ोत्तरी है 5000 करोड़ रुपये के करीब। दूसरा सरकार की कोई तेल नीति नही है। जिस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल खरीदा जाता है, सौदे होते है, यह ऐसा नही करते, यह फ्युचर के हिसाब से, भविष्य के हिसाब से सौदे नही करते है। वहां पर एक सिस्टम है जिसको फ्युचर एड आप्शंस कहते है, उसके हिसाब से सौदे होते है। उस सौदे में यह सरकार सक्रिय हिस्सा नही लेती है नतीजा यह होता है उसमें उस मौके का फायदा नही उठाते जिनका फायदा उठाया जा सकता है, किसानों को राहत दी जा सकती है और उपभोक्ताओं को राहत दी जा सकती है। यह बड़े खुश हो रहे है कि ट्रकों की हड़ताल खत्म हो गई, ट्रकों की हड़ताल का सवाल नही है, वह तो खत्म होनी ही थी। वह तो अपना भाड़ा बढ़ा देंगे और सारी चीजें महंगी हो जाएंगी लेकिन सवाल तो उपभोक्ताओं का है, सवाल उन किसानों का है जो इसके ऊपर निर्भर करते है श्रीमन, इसके साथ-साथ किसानों को इससे दोहरा नुक्सान होने वाला है। इससे पार्म्पिग सेट के जो इंजिन है वह भी खराब हो जाएंगे क्योकि डीजल में जो भारी मिलावट होती है वह और बढ जाएगी। इतना फासला मिटटी के तेल और डीजल की कीमत में हो गया है, मेरा अनुरोध है कि भविष्य में वहां पर जो सिस्टम है फ्युचर एंड आप्शंस का उसमें आप सक्रिय हिस्सेदारी करें। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि कम से कम 600 करोड़ का समायोजन उसमें कर दें और तीसरा यह है कि वृद्धि जरुर करें लेकिन वृद्धि ऐसी करें कि किसी को अखरे नही और विशेष रुप से किसानों को कोई परेशानी न हो।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I wish this discussion would had taken place earlier here, in a full House, because it is not only a question of diesel price rise. It is a question where I find deception, deceit and hoodwinking have been going on, in the name of import parity. First and foremost, who had taken the decision to raise the price of diesel? Here, I would like to refer the Economic Times of 6th October. They say that the price rise was announced by the Oil Coordination Committee Executive Director, Shri M.S. Ramachandran. Shri Ramachandran says, and I quote, "The decision has been taken by the OCC. The Cabinet has nothing to do with this." Shri Ramachandran said it at a press conference. What does it mean? Is it the decision of the OCC or, is it the decision of the Government? But after it was raised, first there was that mask that it was not a Government decision, it was the OCC which had done it. When the question was raised and the pressure came to reduce it, then, the Government, not the Government even, the Minister comes, the Prime Minister comes, and says, "No, no, it cannot be reduced. It is.a decision." The Minister must clarify the first point. If the OCC chief had said, whosoever he is, that this was his decision, the Parliament can overrule this decision, the Government need not come in between; otherwise, the Government must take action against this gentleman who had said that it was OCC decision, and not a Cabinet decision. It is a very important point.

Now, I come to another point. I have got this Note which has been referred to by the Minister. I am sending a letter to him right now. This hides more, and reveals less. Come to para 8; Shri Kaushik was also referring to it. This is not fair. Let us be transparent, I am not a party. This is not transparent. You have given a list of the revision of price from September, 1997 to 1999, as per import parity. Fair enough. It is as per import parity. You have not given the price, international price, as per which this price has been revised. Why? Why have you not given the price based on which this revision has been made? You are not transparent to the Members of Parliament also. You say that the whole thing had been discussed based on Feb., 1999 price *vis-a-vis* September, 1999. There has been a rise in the international price by 114 per cent; so we have raised by 66 per cent; we have raised it by 40 per cent, and all that but what has been the corresponding price after these nine revision which took place from July, 1997 onwards? I will give you one example as to what exactly is being played and how you are hoodwinking the people. On 2nd September, 97, when the import parity policy was announced, what was the international diesel price? The international diesel price was 163 dollars per metric tonne, and what was the poor consumer paying in the market? I have got the figures of Mumbai, and the poor consumer was buying one litre of diesel for Rs. 11.53. After the revisions has taken place! During 1998-99, when this Government was in

power, it was the lowest, it was climbing down all the time; and what was the lowest diesel price? I am talking of import parity; I am not talking of U.F, and all that. It is a question of deceit and deception. When the revision took place in Feb., 99, it was 83 dollars. It was 163 dollars in 1997, and the Consumer price in Mumbai was Rs. 11. 163 तब भी तब भी 11. Now, I start from 83 onwards, February onwards. This is my parameter; this is my benchmark, and now I tell the people that from 83 dollars, now it is 163 dollars. How can the country cover this much of oil pool deficit? So, today, for the same price of 162 dollars, the consumer in Mumbai has to pay Rs. 16. How do you justify it? You cannot justify it even as per the reformer's policy. I know he is not responsible for it. He is a very nice man. I know him. He is not the man to reply to the debate. That is why I feel pained. The fellow who is supposed to reply here today is the reformer, the second stage reformer, the performer, as per the Confederation of Indian Industry.

He is responsible for this, and not this poor man, the Petrolem Minister. I am sorry to say this. Not this poor man, the Petroleum Minister, but the Government, as a whole.

SHRI RAM NAIK: Yes, you are right I am a poor man.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I wish the Prime Minister were here. Even the Leader of the House can reply. I saw him noting down points.

Do you call this import parity? The major problem is in the Budget. The basic price has been changed. With regard to other things like price and excise duty, they have been adjusted. So, the consumer does not get any relief. What does the Budget say? I am a consumer and not a politician. In the Budget of 1999-2000, Mr. Yashwant Sinha, the reformer and the performer says with regard to import parity: 'Currently, international and domestic prices of crude oil and petroleum products are soft.' Mark the word 'soft'. He further says: 'It is, therefore, felt that raising some additional revenue through this commodity would be an equitable method of resource mobilisation.' Well, that is the point. Then, why are you talking of import parity and all that? If the price is soft internationally, what he proposes? "I propose an additional duty of one rupee per litre on the domestic industry." When the internal price is soft, it is not Mr. Ram Naik, Mr. Yashwant Sinha will come here and say, 'One rupee per litre is soft.' And, when the international price is very low there will be one rupee per litre extra. The consumer does not know what the basic price is. Before that, he said, "I had already levied one rupee per litre with effect from 2nd June, 1998." So, from 1998-99, it is two rupees. Courtesy, the reformer and the performer! Then, when the market becomes hard, from 83 dollars to 160 dollars, then Mr. Naik comes here: 'This is the import parity and so I put another three rupees.' This is how you are trying to fool the people. And how long can you fool them?

Then, I come to the next. What about this oil pool? Everyone is talking about the oil pool. This is what has been told in the Fourth Report of the Standing Committee on Petroleum and Chemicals. It was a Committee wherein there were 45 members, inclusive of all parties. Some of them are now ministers in your Cabinet. At page-8 it says, "The Committee regrets to note that the Government allowed to accumulate oil pool deficit thereby delaying payment of huge amount of Rs. 12,000 crores to oil sector PSUs. The Government has assured the Committee that now onwards, deficit will not be allowed to occur.' This Government has assured the Committee that oil pool deficit will not be allowed to occur. I think, it is a breach of assurance. Further, the Committee says, "The Committee recommends that the new concept of zero deficit should be ensured through enhanced efficiency of the oil sector and not by increasing the prices of petroleum products every now and then." This is what you did in the name of oil pool deficit! Why this oil pool deficit has occurred, despite this assurance to the Standing Committee? This is my point.

The oil companies had some problem. They did not have money to even import the crude oil, unless this price hike was effected. Is it not a point? It is one of the points. It is your Government. I do not know whether you know about cross holding of equity between oil companies. Who did it? It was your Government. What was done? I do not know how many of the Members are aware. In spite of having disinvestments, reasons were not found proper. What was done is a big story.

The IOC will sell its shares to the ONGC and GAIL; the ONGC will sell to the IOC. The IOC had to pay Rs. 2475 crores for buying shares of the ONGC and the Gas Authority. The ONGC had to pay Rs. 1622 crores for bying the shares of the IOC and the Gas Authority. The GOI had to pay about Rs. 400 crores to buy the shares of the ONGC. The total comes to more than Rs. 4000 crores. Your Finance Minister had no business to grab this money of the oil companies. This has been done. Now they say that they do not have money. Sir, as a result of this, the market capital value of these companies has gone down. These are Government shares. This money belonged to the oil companies. Who stopped them? In this very House, when the United Front Government was only three months old, late Mr. Satish Agarwal had challenged, and challenged very correctly-^we were with them; at that time, we were together, in spite of the fact that we were giving support to that Government—and said that this amount of Rs. 4000 crores which belonged to the Oil Pool Account was a misappropriation of money and the United Front Government must see that this money was again appropriated. Have you appropriated that money that has been withdrawn by the Finance Ministry from the Oil Pool Account? Or is it the case that when

you are in the Opposition, you say something, and when you are on that side of the House, you forget about it? What about the Oil Industry Development Act, 1974? As per the OID Act, how much money has been collected and how much money has been given to the petroleum sector? Sir, in its 7th Report which was placed before the Parliament on 17th March 1999, the ,Standing Committee on Petroleum and Chemicals recommended: "The Committee specifically recommends that so far as the OID Act is concerned, the Government must give back the money which was collected as cess under the Oil Industry Development Act." On 31st March, 1998 this amount was Rs. 3163 crores. This amount was collected under the Oil Industry Develop- ment Act. Out of this only Rs. 902 crores, have been given for the improvement of the oil sector. The Committee had quoted all this from the Report of the CAG which says, "The funds generated from the cess, the cess collected under the Oil Industry Development Act, 1974, are largely not being applied for the purpose for which it is levied. The imposition of cess itself loses much of its justification. "Why don't you remove this cess? The cess is Rs. 60 per tonne of crude oil produced. This money should go for the development of the petroleum sector. But it has gone to your performers and reformers, or, to the Consolidated Fund of India. Why do you say that the petroleum sector has not money when that money has not been utilised for that particular sector? Now you say that this cess must be removed and the consumer given that much relief. Who stops you from doing that? If you cannot reply to that, then, let the Finance Minister or the Prime Minister himself come and reply to it. So, Sir, this is the case about this money. I have already referred to the speeches regarding the options. Are they really interested in the options; as a country, are they really interested in the options? During the 8th Plan, we were drawing about 60 per cent of our petroleum and oil products by import and the total value would be about Rs. 28,000 or Rs. 30,000 crores or whatever it is. In the 9th Plan, are going to depend on import to the tune of 70 per cent, which means 70 per cent of oil will imported. This is the 9th Plan evaluation. Our oil production is not increasing. It is decreasing from 32 million to 30 million. You know this. You are talking of a nuclear deterrent.

5.00 P.M.

The other day, Mr. Murli Manohar Joshi very correctly said in the Lok Sabha. Will you please allowe me to quote from his speech made in the Lok Sabha .... *(Interruptions)* .... अगर आप नही सुनना चाहते तो मत सुनिए, लेकिन फिर ऐसी डिबेट करने से फायदा क्या? जो बढ़ा दिया, वह तो बढ़ा दिया और आप नही घटाएंगे, यह भी बोल दिया। हम लोग डिबेट करते है ...(**व्यवधान**)... नही, सुनने का कोई फायदा नही है और अगर सुनने का कोई फायदा नही है तो फिर यहां से क्यों बोलते थे आप? क्या क्रेडिब्लिटी है आज, अगर अपोजिशन में आप कुछ बोलेंगे और यहां से कुछ और बोलेंगे? On 15th July, 1996, I had

given the report. Please go through the proceedings. He had mentioned about demand management. I had said here also. Yes, demand management is one of the options. Do you really bother about these options? 70 per cent import will do. You are talking about a nuclear deterrent. What is your oil deterrent? If you are sorrounded by American ships for seven days, you will not be in a position to have a war. You are talking about a nuclear deterrent. But you are not talking as to what will be your oil deterrent. What is energy audit? In that meeting, when the Deve Gowda Ministry raised the price, we had proposed a mandatory energy audit. How many of your industrial friends or advisers are having mandatory energy audit? Do they talk about it? They talk about it in their annual reports and show something. But do they do annual energy audit at any time? Have you been talking about those mandatory energy audits at all? You are depending 70 per cent on import. It is not a-question of rupee cost. It is known as petro cost. We are bothered about petro cost. Fifteen per cent population of this country can afford this hike of 40 per cent. Those who support the Press, the TV, do not talk about this. They know about it. They will not talk. Then, what is happening in the name of this? They can afford this 40—45 per cent price hike. But the nation cannot afford this petro cost. What is our petro cost? How are we saving? What is our demand management? You have set an example, your new Government have set an example, so far as petro cost is concerned. Have you done any energy audit for a Minister? How much petrol is required? How much diesel is required? Energy audit means energy efficiency in every office, in every company. How much energy you are consuming? You have increased your Minister to 70, with 26 Secretaries extra. This is the petro audit!

और गौतम जी बोल रहे है, काहे को पढ रहे है? हम एम.पी. है हम क्या बोलेगे जाकर के, बोलिए?

One air-conditioned bus has been provided to Parliament. My heart is burning.

एक लीटर से दो किलोमीटर भी नही जाती और जैसे ही सैशन खत्म होगा, हम लोग जाएंगे, हम लोग बैठेगे उस गाड़ी में जो एक लीटर से दो किलोमीटर जाती है और ये 70 मंत्री होंगे, उसके पास अगर 45 मिनिस्ट्री भी होती है, इन्फारमेशन टैक्रोलॉजी की मिनिस्ट्री आपको दे देता हूं एक्स्ट्रा से, could you not manage this country with 45 Ministers, so many Secretaries, do you know how much diesel is used? हम जब अपोजिशन में रहेंगे तो बोलेंगे कि नही बढना चाहिए और जब हम वहां रहेंगे तो कुछ और बोलेंगे? यहां तो मेरे पास लीडर आफ दि हाऊस का बयान भी है। I will quote from Mr. Jaswant Singh's speech made in Lok Sabha on 15th July, 1996. Of course, he was the Chairman of the Standing Committee on Energy; he was my Chairman. I have great regard for him. He said, "There are two issues involved. Firstly, whether the reference to noting on files is a matter that

should be discussed or not. The second thing is that I have been asked by my senior colleague as to whether I had made any recommenation of this nature of a sudden steep hike. No, Sir. I certainly expressed my grave concern at the deteriorating situation that the deficit would go up to Rs. 11 thousand plus crores. So, Sir, Shri Jaswant Singh as the Finance Minister for thirteen days had at that time expressed his anxiety that the Oil Pool deficit might go up to Rs. 11,000 crores. But, then what did he say? "It is an estimate". Certainly, it was on record, that if corrective action was not taken, the situation would be difficult. But that corrective action will be a 30% hike was certainly not a part of our noting. We would have found out alternatives of doing it, not doing it on the eve of the Budget Session of Parliament. You said you had a set of options. I woul like to know, what has happened to those options. If those options are only in your pocket, please expose ihem to us, what options you had at tha* time, in 1996, that oil pool deficit of Rs. 11,000 crores could have been managed without a price hike which the United Front Government had to do. This is the credibility. If we cannot do it, we have meetings, we have debates, we have discussions, we have performers, reformers. There is no idea. There is no reason why we should have this 40% hike. If 163 dollars was the international price in 1997, and, today, it is 167 dollars again, either you should have the courage to say "we have resource problems; my reformer and performer has put the country in such a way that the rupee has been devalued". This is what the point is. The import duty value has increased. You should have said, "I have no other way to earn revenue and this is the way I have to earn the revenue". If resource mobilization was the point, why don't you seek the help of your advisors? Rs. 45,000 crores worth of non-performing assests are there. Can't you have the list of those dodgers? Ask them to give the money. Whatever they have taken from the banks, can't you get that money back? You should tell them that this is bank's money. Your Government has given the bail-out package to these companies who have diverted the money. Mr. Naik, in your Mumbai, money has been diverted. Money is taken out of the steel sector. Rs. 99 crores have been diverted and those fellows have been given a bail out package of Rs. 5400 crores. You can bail out the steel sector, you can bail out the telecom sector, you can bail out all these industrialists. But when the question of money comes, you say, "I do not have the money". You have raised this money by way of increasing Rs. 3 per litre in diesel. Is this the only alternative way of resource mobilization? You said, "We have no other way". You should say, "We are industry-friendly and we can do anything at the cost of the poor; and we remember the poor only when the election comes; and at that time, we have our own signals". But you have no business to talk about import parity, budget and other things to justify this price hike. This price hike in diesel is a source of mobilization at the cost of poor)

people, leaving out the rich, which is an atrocity. This must be reviewed. Thank you, Sir.

**श्री राधाकिशन मालवीय (मध्य प्रदेश)** : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जिसका असर इस देश की आम जनता पर पड़ रहा है। महोदय, सरकार ने यह कहा कि हमारे ऑयल-पूल में घाटा होने की वजह से हमने डीजल के दाम बढ़ाए है और डीजल के दाम बढने से सरकार को 6,600 करोड़ रुपए का लाभ होगा। महोदय, लाभ उन्होने जरुर देखा मगर इस देश के करोंड़ो लोगों पर डीजल के भाव बढने में कितना असर पड़ रहा है, इसकी तरफ सरकार का ध्यान नही गया।

महोदय, अप्रैल के बाद, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर तक केयरटेकर गवर्नमेंट के रुप में यह सरकार थी, मगर इन महीनों में इन्होंने दाम नही बढ़ाए। जब इस देश की जनता चुनाव परिणाम की तरफ देख रही थी कि लोकसभा में क्या नतीजा निकलने वाला है, 6 तारीख के दिन गिनती शुरु होनी थी और 5 तारीख की आधी रात को इन्होंने दाम बढ़ा दिए। उस दिन देश की जनता का दिल और दिमाग चुनाव परिणाम की तरफ था। बड़ा सोच-समझकर इन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया कि दो-चार रोज तक तो कहीं हार कही जीत, इस तरफ था। जनता का दिल और दिमाग रहेगा और बाद में यह मामला ठंडा हो जाएगा। और भाव को उन्होंने बढ़ा दिया। मगर इस भाव से जैसा मैने पूर्व में कहा है कि हमारी आम गरीब जनता जो है उसके ऊपर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हमारे किसान भाइयों के ऊपर। राघवजी यहां पर नही है। उन्होंने जो बात यहां पर रखी मुझे उनकी बात सुनकर के बहुत दुख हुआ कि किसान को ट्रेक्टर नही रखना चाहिए। दस-दस और पन्द्रह एकड़ जमीन वाले ट्रेक्टर रखते है और डीजल के भाव बढने से उनकी पुर्ति नही होती, यह घाटे का सौदा है। उनकी यह अच्छी बात नही है। आज किसान अगर सक्षम बनता है, अगर वह आत्मानिर्भर बनता है, वह अच्छी खेती करता है तो हमारा देश खुशहाल होता है। अगर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ा, हमारी गरीब जनता के ऊपर पड़ा क्योकि डीजल के भाव बढने से आम उपभोग और उपयोग की जो चीजें है उसमें अपने आप भाव में वृद्धि हो जाएगी, उसका सीधा असर हमारी गरीब जनता पर होगा।

मै मध्य प्रदेश से आता हूं और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है। अभी इसके पूर्व उड़ीसा में साइक्लॉन के ऊपर यहां पर बहस आज चली। मगर मध्य प्रदेश के ऊपर भी अब के अति वर्षा का प्रभाव पड़ा। आज सोयाबीन की फसल चौपट हो गई और जबकि अब किसानों का खेती करने का इस समय सीजन आया है और इधर डीजल का दाम बढ गया है। पूर्व की जो सरकार थी उसने सोयाबीन का दाम 1100 रुपए और 1200 रुपए क्विंटल तक हमारे किसानों को दिया। लेकिन अब भारत सरकार ने जो इसका समर्थन मूल्य निर्धारित किया है वह 835 रुपए क्विटंल है और आज मध्य प्रदेश में मंडियों में सोयाबीन 400 रुपए के भाव पर बिक रहा है। कुछ समझ में नही आता। इस प्रकार वहां का किसान दोहरी मार से मरा है। एक तो उसकी सोयाबीन की फसल नष्ट हुई और मंड़ी में भी उसका सही भाव नही मिल रहा है तथा दूसरी तरफ डीजल के भाव बढ रहे है जबकि उसका अब खेती का सीजन शुरु हुआ है। अगर भाव भी बढ़ाना था तो कोई एक रुपया दो रुपया बढ़ाते। हमारे दीपांकर साहब ने बहुत अच्छे पोइंट इसमें कवर किए है। 124 डालर का इसका भाव था।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल का भाव बढ गया 163, उन्होंने सीधे 33 प्रतिशत इसमें वृद्धि कर दी। अगर इसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो डीजल का भाव दो रुपए प्रति लीटर से ज्यादा नही बढ सकता था। मगर इसमें चार रुपए की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि की सीधी जो मार अगर किसी पर है तो हमारे किसान भाइयों के ऊपर सबसे ज्यादा है क्योकि अब उसका खेती का सीजन होगा। उसका पानी का इंजन डीजल से चलता है, उसका ट्रेक्टर डीजल से चलता है। इधर वह अतिवृष्टि के कारण मार खाया हुआ ही है उधर डीजल के भाव बढने से भी उसको काफी नुकसान हुआ है। मै सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों के हित में कुछ न कुछ जरुर निर्णय लें। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि अब डीजल के भाव में कोई कमी नही होगी और पैट्रोलियम मंत्री साहब भी बैठे है, उन्होंने भी कहा है। मगर आपको विचार तो करना ही पड़ेगा अब इसके बाद में हमारा रेल विभाग ही आएगा। क्योकि उसमें भी डीजल का इंजन चलता है और जब भार रेल के ऊपर आएगा तो किराया भी उसका निश्चित रुप से बढ़ेगा। तो डीजल की वृद्धि का सीधा प्रभाव हमारे लाखों लोगों के ऊपर डायरेक्ट-इनडायरेक्ट पड़ेगा। मै तो इस सदन में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे पैट्रोलियम मंत्री जी यहां बैठे है, मेहरबानी करके जितना आप कम कर सकें डीजल के भाव को आप जरूर कम करें। धन्यवाद।

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the recent steep hike in diesel price is a very serious matter. It is a serious matter for the Government because there was no alternative to reduce the oil pool deficit except to hike the price of diesel. It is also a serious matter for people because it increases their hardships and makes their lives miserable. The Government have effected hike only on diesel price, but this hike is so. powerful that it had a cascading effect on all the consumer goods, including foodgrains, vegetables, freight tariff and passenger tariff. We understand and appreciate the reasons for this steep hike. But we are unable to appreciate the manner in which it has been done. One, the Government should not have taken this decision so hurriedly, even when the verdict of the people was in ballot boxes and could have waited for some more days. Two, the hike at a stretch was a painful decision. It could have been effected in 3 or 4 instalments. Three, the Government could have told the nation the necessity and the compulsion of hike and could have discussed with political parties. The demand for diesel consumption is likely [k] to go up from 37.5 million tones in 1998-99 to 40 million tones during the current financial year. I believe that more than 50 per cent of petrol and diesel is consumed by the Governemnt vehicles. Vehicles are provided to the Government officials for discharging their official duties, but wc find these Government vehicles at the Government schools, private schools, shopping centres, vegetable markets, cine theatres, hotels and sometimes near bars also. I request the hon. Minister to give a serious thought and try to reduce the use of Government vehicles for private purposes.

Whenever there is an increase in the oil price in the international market, the Government resorts to an increase in the oil price in the country. Instead

of doing that, the Government should consider other measures like increasing the domestic oil production and reduce imports, as much as possible.

I also request the Government to seriously consider supplying diesel, at least, to the public transport vehicles on subsidy, on par with other items, through the public distribution system so that poor people are not affected with the hike.

There are indications that the LPG price would also be increased. Our State Government is in the mid-way of providing 10 lakh LPG gas connections to the poor families living in the rural areas. Therefore, I would appeal to the Government not to hike the price of LPG and kerosene.

**श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश)**: उपसभाध्यक्ष जी, सरकार चाहे हमारी हो चाहे इनकी हो, प्रदेश की हो या केन्द्र की हो, सरकार को विकास के काम करने पड़ेंगे। नई योजानाएं क्रियान्वित करनी पड़ेगी, संयंत्र लगाने पड़ेंगे, इन सबके लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा, खचें कम करने पड़ेंगे, राजस्व का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा? कोई घोटाला तो नहीं हो रहा? भ्रष्टाचार तो नहीं हो ? मंत्रियों की जेब में तो पैसा नहीं जा रहा? यह हमें देखना है और इस मामले में जिस मद से जिस क्षेत्र से राजस्व आया है, उसका अधिक भाग उस क्षेत्र में जाना चाहिए। एक तो मेरा यह निवेदन है।

महोदय, पहली बार एक धर्म की बात इन सी0पी0एम0 वालों ने कही। वैसे तो हमेशा इनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहा है, कभी सकारात्मक दृष्टिकोण मैंने तो दस साल से देखा नहीं है लेकिन आज एक अच्छी बात इन्होंने कही, हम शुरुआत यहीं से करेंगे। हम शुरुआत पार्लियामेंट हाऊस से ही करें। पांच मेटाडोर यहां मौजूद हैं सांसदों को लाने ले जाने के लिए। पहले एक थी और वह भी एक-एक को ले जाकर कई चक्कर लगाती थी और डीजल बरबाद होता था और अब पांच आ गई। यह डीजल की बरबादी है। इसकी खपत को हमें कम करना चाहिए इसलिए हम संसद भवन से ही शुरुआत करें। चलिए आज ही से करें। क्या जरुरत थी इन मेटाडोर्स की? ये खड़ी रहती है, एक-एक आदमी को ले जाती है, छोड़ती हैं। इस प्रकार डीजल की बरबादी हो रही है। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीजे ऐसी हैं जो हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं। हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थो का उत्पादन कम है। हम आयात करते है तो हम यह आयात कम करें और राजस्व न लगाना पड़े, कीमत न बढ़ानी पड़े, इसलिए हमें खचें कम करने चाहिएं। एक तो आपने यह बताया कि कारों पर खर्चा कम होना चाहिए। अगर एक मंत्री का काम एक कार से चल सकता है तो उसे दो-तीन या चार कार रखने की जरुरत नहीं है। इसके लिए मैं अपनी सरकार के मंत्रियों से प्रार्थना करुंगा। यह बात भी सही है कि मंत्री परिषद् में मंत्रियो की संख्या कम होनी चाहिए लेकिन जमाना ही ऐसा आ गया है, 537 सांसदों पर 70 मंत्री है और महाराष्ट्र में 288 विधायकों पर 70 मंत्री हैं। यानी काने को काना कह रहे है। आपके बिहार में 324 विधायकों पर 77 मंत्री थे। यहां तो मजबूरी है क्योकि बहुत सारे दल हैं। लेकिन फिर भी ...(व्यवधान)... मैं आपकी बात से सहमत हूं कि परिषद् में मंत्रियों की संख्या कम होनी चाहिए।...(व्यवधान)...

**श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश)**: आप भी शपथ के बाद बोले हैं गौतम जी।...(व्यवधान)...

**श्री संघ प्रिय गौतम**: मैंने तो यहां आकर दो बार शपथ ले ली है। और जब तक जिंदा रहूंगा लेता रहूंगा।...(व्यवधान)...

**श्री सुरेश पचौरी** : कांग्रेस वाले आपका समर्थन करते है।...(व्यवधान)...

**श्री संघ प्रिय गौतम**: जो सांसद दूर के रहने वाले है और जिनके परिवार दिल्ली में नही रहते हैं उन्हे दिल्ली में कार नहीं रखनी चाहिए और उन्हे डीजल बचाना चाहिए। एक परिवार में पति-पत्नी और दो बच्चे हैं अगर उनके पास एक व्हीकल से ज्यादा है तो बाकी व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन केंसल कर दिये जाने चाहिएं। आप लफ्ज़ों के जाल में लोगों को फंसाते हैं, आंकड़े पेश करते है 'लैट अस बी प्रेक्टिकल इन रियलिस्टिक'। हम तो करें नहीं और भाषण करें तो लोगों को दिखाएं कि हमने कितना बड़ा भाषण दिया। हम आज से यहां शुरु कर देंगे।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)**: बस हो गया गौतम जी। श्रीमती कमला सिन्हा।

**श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार)**: उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां बहुत बाते हुई हैं और कई तरह की चर्चा चली है। बहुत ही अच्छी तरह की बातें हो गई है विस्तार से। मैं उन सभी बातों को दोहराना नही चाहूंगी। मुझे दीपांकर जी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिनों के बाद मैं भी उनके साथ गेट मीटिंग में भाषण सुन रही हूं। 'आई एप्रीसिएट योर स्पीच वेरी मच।' यह ठीक है कि हमारे यहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्रस की कमी, है और जितनी देश को जरुरत है उससे एक तिहाई ही हम उत्पादन करते हैं। यह भी सही है कि हमको दुनिया के बाजार में ओपेक कंट्री से खरीदना पड़ता है और वे जो प्राइस तय करते है उसी के आधार पर हमें खरीदना पड़ता है 'वी हेव नो अदर च्वाइस।' अगर हम पिछले दिनों का विश्लेषण करें तो पायेंगे कि लगातार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी बढती गई है। यह कोई हाल की घटना नहीं है। लगातार प्राइस बढ रहे हैं। मुझे तो याद है एक जमाना था जब एक गैलन पैट्रोल 12 आने में मिलता था लेकिन आज उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। चार रुपए या पांच रुपए बढ़ा दिए है। साढ़े तीन रुपए से साढ़े चार रुपए की डीजल में वृद्धि हो गई है। यहां माननीय सदस्यों ने कहा कि डीजल की वृद्धि से आम जनता के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यह बात सत्य है क्योकि बसों के किराए बढ गए और जो लोग डिस्टेंस ट्रांसपोटेंशन के लिए हम सफेद ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते है, खासकर लैड ट्रांसप्रोर्ट के ऊपर उसके कारण भी सब सामानों के दाम बढ़ेंगे। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आम नागारिकों का जीना मुश्किल होगा। खासकर के जिनकी समयबद्ध आय है, जो सरकार नौकरी-चाकरी करते है या जो फिक्सड इनकम ग्रुप के लोग है उनके लिए बहुत दिक्क्त की बात होगी। ग्रामीण अंचलों में केरोसिन की खपत अधिक है क्योकि दूर-दूर तक चले जाइए आपको कही रोशनी नही दिखेगी। इस देश में बिजली की कमी है। जितनी बिजली चाहिए उतना बिजली का उत्पादन नही होता है। यदि मै अपने बिहार प्रांत की बात करुं, हमारी ढ़ाई हजार मेगावाट मिनिमम रिक्वायरमेंट है जबकि उत्पादन है तीन सौ, साढ़े तीन सौ मेगावाट। दूर-दूर तक चले जाइए कही रोशनी नही दिखेगी, दीया भी नही दिखेगी, यह हालत है। केरोसीन की कीमत को एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के तहत कम रखना पड़ता है सरकार को क्योकि यह आम आदमी के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। एल.पी.जी. की भी वही हालत है, जलावन के लिए मिलता नही है कही पर जितने जंगल काट सकते थे हमने काट डाले है। आज ही बाढ के बारे में बात करते हुए माननीय सदस्य जस्टिस मिश्र जी ने बताया था कि हमारे देश में 33 प्रतिशत जंगल का फोरेस्ट कवर अब 19 प्रतिशत कम हो गया है। जंगल भी हमने

काट डाले। लकड़ी नही है जलाने के लिए कोयले की कमी हो रही है। हम विदेश से 25 परसेंट कोयला आयात कर रहे है अपने देश की रिक्वायरमेंट के लिए। नतीजा है कि एल.पी.जी. के बगैर काम नही चलता। खासकर के शहरी कस्बों में अब एल.पी.जी. चूंकि साधारण जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है इसलिए उसकी कीमत को भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजस के तहत कम रखना पड़ता है। नतीजा है सारा बोझ पड़ता है किसानों के ऊपर, छोटे-छोटे शहरों में रहने वाले और बड़े शहरों में रहने वाले लोगों पर। मै किसानों की बात इसलिए कह रही हूं क्योकि पिछले दिनों चुनाव के दौरान जब मै जा रही थी, गाव-गाव घूम रही थी तो कई जगह मुझे लोगों ने कहा कि हमारे यहां बिजली का तार आप देख रही है, बिजली नही है। किसानों को कम दर में बिजली किसानों को सिचाई के लिए देना है, वही भी नही हो पाता है। हमें डीजल महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है और खेती का काम करना पड़ता है। खेती के काम के लिए डीजल की जरुरत है, बड़े पैमाने पर जरुरत है। अब हम भी परेशान हो जाएंगे यानी कोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिग वुड बी वेरी हाई तो यह ऑल राउण्ड होने वाला है। अब इसका रास्ता कई लोगों ने सुझाया है। मै भी एकाध रास्ता बताना चाहूंगी। जैसे ट्रांसपोटेंशन के बारे में कहा गया है। अगर सरफेस ट्रांसपोर्टर से वाटर ट्रांसपोर्ट हो तो वह ज्यादा अच्छा होगा यह बात सही है कि वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ इण्डिया लि. हमारे यहां बना हुआ है नदियों से सामान ढोने के लिए। साल में नौ महीने निश्चित रुप से उससे काम ले सकते है। यह कोयले से स्टीमर के जरिये चलाया जा सकता है। उसमें डीजल की जरुरत नही पड़ेगी। बल्कि ट्रांसपोर्टेश्न उससे हम कर सकते है, ट्रांसपोर्टेशन करके पाइंट टू पाइंट ट्रक से भेजा जा सकता है, ट्रेन से किया जा सकता है पाइंट टू पाइंट। जैसे हमारे बिहार में पटना से कोई 55-60 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर मुकामा है जो, नीतीश जी की कांस्टिटयेंसी में आता है। वहां से पटना शहर के लिए दूध आता है। तो इस तरह से डेली जरुरत की चीजें, जैसी सब्जी, दूध जो ट्रक में आती है उनको ट्रेन से पांइट टू पाइंट मंगवाकर, उसके बाद डिलीवरी पाइंट पर ट्रक से भिजवाया जा सकता है। उससे डीजल की खपत में कमी होगी। एक साथी ने कहा कि ट्रैक्टर रखने के बाद उसका खर्च बढ जाता है। उसका खर्चा बहुत होता है वह वायबल नही होता है। इसके बारे में सुझाव देना चाहूंगी, पता नही वह हमारे देश में चलेगा भी कि नही। मै बहुत दिनों पहले इजराइल गई थी और वहां के गांवो में मुझे जाने का मौका मिला। मै मुशाद और अन्य जगहों पर गई। वहां पर कोआपरेटिव फार्मिग होती है। गांवो में एग्रीकल्चरल यार्ड थे जिसमें पूरे गांव की खेती का सामान रखा हुआ था, इन्क्लुडिग ट्रैक्टर। जो उसे ले जाता है वह अपना नाम दर्ज कर लेता है और उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको वह वापस कर लेता है। इससे जो प्राफिट होता है उससे उसका खर्चा निकलता है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की कोआपरेटिव्स अगर हम बना सकें एग्रिकल्चरल एक्विपमेंट हम वहां पर रख सकें जिसका इस्तेमाल पूरा गांव कर सके, पूरी कम्युनिटी कर सके तो इससे किसी एक पर इसका बोझ नही पड़ेगा और इससे डीजल पर होने वाला खर्चा भी कम हो सकता है। नही तो हर एक व्यक्ति को डीजल का पम्प सेट रखना पड़ता है, ट्रैक्टर रखना पड़ता है और इससे उसको फायदा नही होता।

दूसरा मै वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में एक बात यहां बताना चाहती हूं कि मै पहली दफा 1988 में चाइना गई थी और उस समय मुझे पूरे चाइना को घूमने का मौका मिला। वहां हमने देखा कि वहां पर एक 16 मीटर ग्रांड कैनाल है जो आज से एक हजार साल पहले बनी हुई थी। वह आज भी बाइबल है। उसके द्वारा सामान यहां से वहां ले जा सकते है। हमारा नदी मांत्रिक देश है। हम अपनी नदियों का

नाम लेकर मंत्र पढते है। तो फिर हम इसको क्यों नही कर सकते? हमारे यहां काम को करने की जरुरत है। कोई भी सरकार हो, कल विपक्षी दलों की सरकार थी, परसों हमारी थी और आज भी हमारी सरकार है, एन.डी.ए. की सरकार है। कोई भी सरकार हो हर सरकार का एक चरित्र होता । सत्ता में बैठे उनको कुछ महत्वपूर्ण काम करने पड़ते है। सरकार ने जो यह किया है इसको क्रिटिसाइज करने के बदले मै यह कहूंगी कि आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए अगर संभव हो तो डीजल के प्राइस थोड़ा रोल बैक कर दें ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

**श्री नरेश यादव** (**बिहार**) : उपसभाध्यक्ष महोदय, डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि उस समय हुई जब कि पूरा देश अपने मतों का परिणाम सांस रोककर जानना चाह रहा था। चुनाव के परिणाम आए भी नही थे कि आपने एक दुष्परिणाम पूरे देश को दे दिया, किसानों और गरीबों की परवाह न करते हुए डीजल की कीमतों में 35 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। यह आपकी सरकार का तेल की कीमत बढ़ाने के मामले में एक रिकार्ड है। ऐसी किसी दूसरी सरकार ने नही किया। इसलिए यह सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, यह कहने में कोई हिचक पूरे हिन्दुस्तान की जनता को नही है। महोदय, डीजल न सिर्फ परिवहन के लिए बल्कि किसानों के लिए छोटे-छोटे उद्योगों के लिए आटा चक्की, तेल पराई के लिए जरुरी है। और यह सब डीजल से सम्पादित हो रहे है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह कहने में कोई हिचक नही है, और आज हम देख रहे है कि इस डीजल वृद्धि का प्रभाच कहां पड़ रहा है। इस डीजल वृद्धि का प्रभाव क्रेता पर पड़ रहा है और विक्रेता मालोमाल हो रहा है। पूरे देश के गरीबों को आज लूटा जा रहा है लेकिन विक्रेता मालोमाल हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योकि यह सरकार विक्रेताओं को लाभ देने वाली सरकार है। यह सरकार पूंजीपरक सरकार है और इस सरकार ने सबसे पहले अपना चेहरा बेनकाब किया है। इसलिए मै यह कहना चाहता हूं की आज किसान हम लोग केला उत्पादक किसान है। जो ट्रक 6000 रुपये में अपना केला देश की विभिन्न मंडियों में भेज रहा था आज सीधे 9000 रुपये ट्रक परिवहन का मालिक मांग रहा है। आज हमारे किसानों के द्वारा उतपादित केला मंडियों में जाता है, किसान के हाथ में कुछ नही जाताअ है, वह खाली हाथ वापस आ रहा है। परिणाम सब के सामने है। महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि यह तुर्रा देते है कि आयल पूल में घाटा हो रहा है। आपकी ओ.सी.सी. ने तीन माह पूर्व ही मूल्य वृद्धि करने के लिए कहा था। उस समय आपने क्यों नही किया? अगर नीयत साफ होती उस समय करते। उस समय देश का घाटा घाटा नही था लेकिन जब मत बक्से में बंद हो , उस समय देश का घाटा आपको दिखाई पड़ गया। इसलिए दिखाई पड़ गया कि आपने जाना अगर मेरी सरकार नही आएगी किसी दूसरे की सरकार आएगी तो उनके माथे पर जाएगा और अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो नक्कार खाने में तूती की आवाज हो जाएगी। यह राजनीति, चालाकी भरी राजनीति कही जा सकती है लेकिन यह श्रेष्ठ राजनीति नही कही जा सकती है। कम से कम आदरणीय वाजपेयी जी से ऐसी कुटिल राजनीति की उम्मीद तो हरगिज नही की जा सकती। मै किसान हूं और इस हैसियत से कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार ने किसान के पेट पर और गरीब की जेब पर लात मारी है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते है कि यह किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है। डीजल के दाम कम करें वरन पूरे देश में जो अग्नि उठ रही है उसमें यह पूंजीपति और सरकार ध्वस्त हो जांएगे। यह मै आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा देश आन्दोलन के लिए तैयार है और उस आन्दोलन को आप बर्दाश्त ही करेंगे। जनता सब से बड़ी शक्ति है, जनता को कोई लूट नही सकता,

लूटना बंद कीजिये, डीजल का जो दाम बढ़ाया गया है, उसको वापस लिजिये अन्यथा जनता बर्दाश्त नही करेगी। देश की जनता तैयार है। आपने गरीबों को मारा है, आपने मजदूरों को मारा है, किसानों को मारा है, हम फिर अपील करते है कि डीजल का दाम वापस करो अन्यथा पूरे देश की जनता खड़ी है इन्कलाब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश)** : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। इस विषय पर सारे सदन में जो कुछ हमारे मित्रों ने कहा है उस पर अपना हस्ताक्षर करते हुए मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। जैसे कि आप सब जानते है कि यह सरकार पेटी में बंद हो कर बाहर आई उसके पहले डीजल की कीमतें बढ गई। डीजल की कीमतों क्यों बढ गई, इस पर नाईक साहब का पेपर हम सब लोगों को मिला है वह आप लोगों ने देखा है, हम सब ने देखा है। जो सारी बातें है मोटे तौर पर मै एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि देश के लोग आपसे यह जानना चाहते है कि इस डीजल की कीमतें बढने के बाद जीवन का कौन सा ऐसा ऐवेन्यू है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसकी कीमत नही बढ़ी? जिन्होंने कीमत बढ़ाई बहुत ही उद्धेलित प्रश्न सामने आया कि मूल बात क्या है? क्या है? क्या इतनी कीमतें सरकार ने बढ़ाई है या प्रशासन के स्तर पर बढ़ाई गई, यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिजन था या केबीनेट का डिसिजन था, इसका फैसला होना चाहिये। कही ऐसा तो नही है कि प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा गया हो, कही ऐसा तो नही कि केबीनेट को भी अंधेरे में रखा गया हो और सक्षम अधिकारियों ने घोषित कर दिया और आपको स्वीकार करना पड़ गया। आप बार-बार, निरंतर यह कहते है कि अब कीमतें वापस नही होंगी, आप कीमतें वापस नही लेंगे। इसके साथ-साथ दो वक्तव्य और चले आ रहे है वित्त मंत्री का भी आ रहा है और प्रधान मंत्री का भी आ रहा है, वह यह है कि कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब आपकी नजर केरोसिन पर भी है और एल.पी.जी. पर भी है और दूसरे ऐवेन्यूज पर भी है। जब टेक्सेशन आएगा तो उस समय आप और विचार करेंगे, सारी बातें करेंगे लेकिन वहां एक मार्जिन है उसके ऊपर में आपको संकेत कर देना चाहता हूं। अभी तक देश की जनता प्रतीक्षा कर रही है शायद इस सदन की बैठक में संसद के इस सत्र में आप कोई न कोई ऐसा फैसला करें जिससे लोग आन्दोलन के लिए अधिक उत्तेजित नही हों। आज कौन सी राजनीतिक पार्टी आपकी या हमारी कोई सी भी पार्टी हो, जो सड़कों पर नही है। सब सड़कों पर है। कही न कही प्रत्येक राजनीतिक पार्टी डीजल के विरोध में इस कीमत के बढ़ाने के विरोध में आंदोलन कर रही है। कौन का किचन ऐसा है जिसमें मूल्य नही बढ़ा हो। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते है, हम भी जानते है टमाटर वापस 22 रुपये किलों तक पहुंच। कोई भी सब्जी आज 10 रुपये किलो से कम पर नही है। उनकी कीमते निरंतर बढ रही है।

अभी यहां पर राघवजी ने जो एक भाषण दिया मैंने उसे गंभीरता से सुना। आप जो कहेंगे हम उसका अनुमान पहले कर लेते है, एण्टीसिपेट कर लेते है कि आप क्या कहेंगे। आप जस्टीफाई करेंगे। लेकिन आग्रह मेरा यह है कि आपकी नीतियों के कारण गए डेढ-दो साल, पौने दो ढाई साल में एक काम होता चला जा रहा है और वह यह कि किचन महंगे हो रहे है और आपके ड्रांइग रुम में रखने वाली जो चीजें है वे सस्ती हो रही है। हमारे किचन महंगे हो गए है। टमाटर 22 रुपये किलो हमने आपने अभी खाए है। दुर्गा की पूजा के वक्त में, गणेश के सममेलन के वक्त में उत्सवों के वक्त में दिल्ली के बाजार में केला नही मिलता था।

सबसे पहला उपहार क्या है आपका देश को? देश को आपने एक उपहार दिया ट्रकों की हड़ताल का। कल मैने देखा और आज के अखबार बोलते है कि ट्रकों की हड़ताल खत्म किस कारण से हुई? भाई नीतिश कुमार जी ने उनको एक खिलौना पकड़ा दिया। अखबारों की टिप्पणियों से लगता है। एक झुनझुन थमा दिया कि हम ट्रांसपोरटेशन को, ट्रांसपोर्ट वाले सारे मामले को उद्योग का दर्जा देंगे और आप जानते है कि यह कितना कठिन काम है। कोई सरकार इस काम को कैसे करेगी। आपसे पहले इन्ही बेचों पर बैठने वाली हमारी एक बहिन होती थी जो सूचना मंत्री थी और मुम्बई में पांच मिनट तक लगातार तालिंया बजी थी उनके वक्तव्य पर कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा दे दिया। क्या आज तक एक इंच भी आगे बढ पाया मामला? नही बढ पाया मै बहुत कम समय लूंगा आपका। मुश्किल से एक-दो मिनट आपसे निवेदन करना चाहूंगा। कौन से एवेन्यूज कौन सा वर्ग है जो प्रभावित नही है। दीपांकर भाई कह रहे थे कि 15 प्रतिशत लोग तो ऐसे है जो सबसे ज्यादा महंगाई भी बर्दाश्त कर सकते है। उनके लिए डीजल आप 100 रुपये प्रति लिटर कर दीजिए तो भी वे खरीद लेंगे। लेकिन क्या हुआ चेन्नई के मछुआरों का। दो हजार मछुआरे हड़ताल पर बैठे हुए थे वे मछली पकड़ तो लें लेकिन खरीदे कौन। मछलियां शाम तक सड़ जाती है।

सब्जियों की मंडी में जब दिल्ली की मुख्य मंत्री शीला दीक्षित जी गयी तो सारे सब्जी बाजार में लोग फूट-फूट कर रोए। क्या कारण था? वहां पर किसानों की सब्जी खरीदने वाला कोई नही। व्यापारी के पास खरीदने की शक्ति नही बची है। सारी की सारी सब्जियों की कीमतें बढ गयी है। सब चीजों की कीमतें बढ़ी है हर किचन महंगा हुआ है और उसके बाद भी आप कहते है इसके ऊपर अभी हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा?

एक तरफ तो आप महामहिम राष्ट्रपति जी से कहलवाते है कि देश की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, कीर्तिमान है। आपने पढ़ा होगा। सभी भाषण देखा होगा। कीर्तिमान है, रिर्कांड है। आप खुद एक तरफ तो राष्ट्रपति जी से कहलवाते है और दूसरी तरफ कहते है कि ये सब मजबूरियां है।

पांच हजार करोड़ का आपका घाटा था आपके तेल पूल का और आपको डर था कि वह दस हजार करोड़ तक चला जाएगाः जब आपके पास यहां वित्तीय स्थिति मजबूत है तब फिर इस दिशा में आपने क्यों सोचा? अब सब्सिडीजपर विचार कर रहे है। इधर-उधर से आप सब्सिडीज वापस लेंगे। आपके समर्थक और प्रशंसक उपदेश देते है कि दस हेक्टेयर से कम वालो को ट्रेक्टर नही रखना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, डीजल की खपत बढ़ेगी आप चाहें जितना कर लिजिए। डीजल की खपत तो बढती चली जाएगी। वह कभी कम नही होने वाली है। लेकिन उस दिशा में यदि आप अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से इसका अनुपात जोड़ते है तब फिर आम जनता के पक्ष में आपकी मूल्य नीति इतनी संतुलित होनी चाहिए कि लोगों की परचेजिंग पावर पर आप हाथ नही डाल सकें। लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हो रही है। किसान उत्तेजित है, किसान आंदोलित है। कही सूखा है, कही बाढ है। किसान पीड़ित है। आप शहरों में जाइए हर दुकान के बाहर कम से कम एक डीजल सेट लगा हुआ है जहां से जनरेटर चल रहा है। बिजली की कमी है। किसी प्रदेश में आप जाइए। इस तरह से अगर आप डीजल के मूल्यों पर पुनर्विचार नही करेंगे तो अगला सेशन जब आपका होगा तो इस सेशन और अगले के बीच में मेरा ऐसा विश्वास है कि राजनीतिक पार्टियां अधिक संजीदगी के साथ सड़कों पर आएगी और कोई सी भी सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, वेस्ट

बंगाल की हो, कर्णाटक की हो, कही की भी हो, उन सरकारों के सामने कानून और व्यवस्था की स्थितियां पैदा होती जाएंगी। आपकी नीतियों के कारण हम सब लोग आहत है। आपने जो 35 प्रतिशत बढ़ाया है वह बहुत ज्यादा है। आप पुनर्विचार करें, हम आपसे आग्रह करते है, अपील करते है। यह 35 प्रतिशत बढ़ाकर आपने किसानों के ऊपर, आम उपभोक्ता के ऊपर जो वजन बढ़ा दिया है उस पर आपको पुनर्विचार करना होगा क्योकि अगले महीने वापस संसद का बड़ा दिया है उस पर आपको पुनर्विचार करनाअ होगा क्योकि अगले महीने वापस संसद का बड़ा सत्र बैठने वाला है और तब-तब ...(**व्यवधान**)... नाईक साहब आप तो मुफ्त में मारे जा रहे है हम जानते है कि आपका डिर्पाटमेंट चेंज नही होता तो आप यहां नही होते। आपको तो विरासत में यह सब कुछ मिला है। इसलिए मै जानता हूं कि आपकी लाचारियां क्या है, मजबूरियां क्या है। लेकिन कृपा कर इस मामले को कैबिनेट में ले जाकर उस का फैसला

करवाइए। अगर वह केबिनेट का फैसला होता है तब तो फिर आप जो हुक्म दे रहे है वह ठीक होता है।

महोदय, मै बहुत पीड़ा के साथ अंतिम बात कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ निवेदन कर रहा हूं कि पेट्रोल पंप मालिकों ने चुनाव अभियान के दौरान हमें संकेत किया था और हम से कहा था कि किसी की भी सरकार बने होली आप ने मना ली, लेकिन दीवाली हम

लोग मनाएंगे। वह कहते थे हम से और तब हम यह समझते नही थे क्योकि हम को विश्वास था। फिर आप ने आधी रात को ही दाम क्यों बढ़ाया? आधी रात को दाम इसलिए बढ़ाया कि वह बिचौलियों की सरकार है और आप उन से चंदा ले चुके थे। अगर चंदा नही लिया होता तो आप शायद यह नही बढ़ाते। आप चंदा ले चुके थे और उन को कोपरेट करना आप की एक ऐसी जिम्मेदारी हो गयी थी कि जिसके बगैर आप काम नही कर पाते।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मै फिर से आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस निर्णय पर गंभीरता से विचार करें और इस निर्णय पर पुनर्विचार कर के इन कीमतों को आनुपातिक स्तर पर, इतने लेवल पर आप ले आएं कि आप आदमी और उस की किचिन सुरक्षित रह सके और इस सरकार को कम-से-कम वह किसी-न-किसी तौर पर धन्यवाद देने की पेशकश कर सके। महोदय, आप ने मुझे समय दिया मै आप का बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

DR. (SMT.) JOYASREE GOSWAMI MAHANTA (Assam): Sir, I would like to share my views with other hon'ble Members of different parties in this August House. Sir, Assam is a petroleum-producing State. From time immemorial, we have been demanding an increase in the rate of royalty. It has also been revised from time to time, but the ratio has not been maintained. Many a time, there is a rise in the price rise of petroleum products, diesel and petrol but the ratio is not maintained. After repeated demands, only sometimes, the royalty is revised. Secondly, Sir, eighty per cent of the people of Assam are farmers. And Assam is also a flood-prone State/ Every year, atleast four-five times it is affected by floods. The people here have no source of income, other than agriculture. So, they arc already very poor, and this steep hike in the diesel price will prove very much dreadful for the people of Assam. My third point, Sir, is, that the people of Assam and the North-Eastern region have to entirely depend on the roadways for transport. Railways are not available everywhere and the areas are also hilly. So, Sir, we arc fully dependent on the roadways, the trucks

and all those means of transport. So this steep hike in the diesel price has created another problem for us. The people of the North-Eastern region have been the worst affected by this hike. Next. Sir. our hon'ble Minister concerned is present here, 1 would say that the capacity of Assam refineries is very meagre. So, this has to be seen and the Government of India should consider the whole thing, so far as North-Eastern region is concerned, because we arc supplying crude oils to different parts of India, fulfilling the needs of other State refineries, through oil pipelines. But in our State, the refineries have a low capacity. This is one important point. Sir. 1 would urge upon the Government on behalf of my party, the Asom Gana Parishad, on behalf of the people of Assam to do their best in revising the crude oil royalty. Also the prices of diesel and other petroleum products should be subsidized for the State of Assam and the North-Eastern region. That is all. Sir.

**श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश)** : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी काफी देर से डीजल के मूल्य वृद्धि पर यहां चर्चा हो रही है और मेरे साथियों ने इस पर काफी विस्तार से चर्चा की है। माननीय मुखर्जी साहब ने तो सरकार के आंकड़ो में सरकार को फंसाने का काम किया। मै सरकार से सीधे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश में डीजल के मूल्य में वृद्धि की गई यानि जब इस देश में चुनाव हो रहे थे, मतदान के तुरन्त बाद, जबकि परिणाम आने बाकी थे, ऐसे समय में डीजल के मूल्य में वृद्धि करना निश्चित रुप से देश में रहने वाले चाहे वह किसान हों, मजदूर हों या आम उपभोक्ता हों, के साथ अन्याय हुआ है। इससे यह जाहिर होता है कि सरकार की मंशा साफ नही थी, उसे न तो आम जनता पर और न ही संसद पर विश्वास रहा था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते है कि आज पूरे देश में, जैसा आप जानते है, 80 फीसदी लोग कृषि पर आधारित है। इस देश में, गांवों में जो बिजली और पानी की हालत है, हिन्दुस्तान का किसान, जैसी चर्चा हो रही थी, पानी के अभाव में रबी की बुआई भी नही कर पाएगा। आज बिजली के लिए नए बिजली घर नही लग पा रहे है, बिजली के खंबे नही लग पा रहे है, पानी नही मिल रहा है। ऐसी स्थिति में किसान ने जो डीजल इंजिन खरीदा है उसका लोन भी नही भर पाया और अब डीजल का जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसे कैसे अदा कर पाएगा। इस नाते, हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते है कि जिस तरीके से यह 35 प्रतिशत की डीजल के मूल्य में वृद्धि की गई है, इससे आम आदमी परेशान है। सीधे सीधे 70 प्रतिशत मालभाड़ा हो या दूसरा भाड़ा हो जिसमें बढ़ौतरी हुई है, चाहे वह बस का किराया हो या आटो का किराया हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें तो यह आशंका है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा घाटे को पूरा करने के लिए डीजल के मूल्य में वृद्धि की गई है, जैसी कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की केरोसिन आयल का भी दाम बढ़ाया जाएगा। इस संबध में मै आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज भी गांव का किसान गरीब है, झोपड़ी में रहता है, उसके यहां बिजली की कमी है और वह अपनी झोपड़ी में दीपक जलाता है केरोसिन आयल का, मिट्टी के तेल का। सरकार ने जिस तरीके से डीजल की मूल्य वृद्धि की मतदान के तुरन्त बाद, आधी रात को, जबकि मतदाना को इस सरकार से बड़ी अपेक्षा थी क्योकि सरकार पारदर्शिता की बात करती है, आम जनमानस चाहे वह किसान हो या मजदूर हो, अपना वोट देकर सरकार

से अपेक्षा करके रात को सोया हुआ था तो जैसे डकैती पड़ रही है आधी रात को यह मूल्य वृद्धि कर दी गई। यह एक कुठाराघात हुआ उसके साथ, उसकी अपेक्षाओं के साथ। इस नाते मै चाहूंगा सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार से, कि सरकार ने जो यह डीजल की मूल्य वृद्धि की है उसे वापस ले, जिससे कि आम जनता को राहत महसूस हो।

इस के साथ धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, actually nobody likes the increase in the price of any commodity, leave aside diesel. But when the circumstances pressurise us and when there is no other alternative, then we have to yield. Earlier the Oil Pool Account was in surplus. If you go through the budget, you will find as to how much amount was actually in surplus in the Oil Pool Account which was shown in the revenue account of the budget to show the minimum fiscal deficit. That has also happened. This was also experienced. Since we have to pay enormous amount for the import of oil, whether the Government is willing or not, they have been forced to pay that amount. That is one reason. However, if any possibility arises due to the international situation or due to any other reason, the hon. Minister will be the first person to reduce the price of diesel. That is my hope. *(Interruptions)* My friend is also supplementing me.

Mr. Vice-Chairman, Sir, today I rise here to reply to some accusations leveled by the hon. Member, Shri Margabandu. When he was speaking a little while earlier, he tried his best to mislead the House by giving some incorrect statistics and worng information. He unnecessarily used the words 'vested interests.' The observation made by the hon. Member is untrue and unwarranted. Therefore *I** totally reject the accusation made against the Government of Tamil Nadu. Since he has leveled these accusations, it is my duty to set the record straight. I would like to give some information to the House. Sir, kindly bear with me. He made two observations, one regarding the hike in bus fare and, two, regarding the hike in cement price in Tamil Nadu. I would like to state here as to how much is the hike in bus fare and what is the price of cement prevailing in Tamil Nadu. The hon. Member said that after the hike in diesel prices, the bus fare in Tamil Nadu was increased by 60 per cent. It is not so. Irt the case of mofusstT ordinary buses, the fare has been enhanced by 18 paise to 22 paise per kilometer. In the case of ordinary buses, the fare has been increased by 19 paise to 23 paise per kilometer. In the case of express buses, it has been increased by 20 paise to 25 paise. In the case of express super deluxe buses, it has been increased by 25 paise to 30 paise per kilometer. In the case of AC express buses, the fare has been increased by 45 paise to 50 paise per kilometer. In the case of express buses, the fare has been enhanced by 25 paise to 30 paise per kilometer. In the case of super deluxe buses the fare has been increase by 30

paise to 35 paise per kilometer. It clearly shows that the accusation made by the hon. Member is callous and unfounded. Apart from this, we have to incur a loss of Rs. 170 crores due to the public transport system.

The hon. Member also mentioned that there is huge hike in the price of cement in Tamil Nadu. This accusation is totally incorrect. Sir, either he should have substantiated his accusation or he should not have made this accusation. Actually, he has made this accusation without knowing truth. 1 would like to made a comparison between the price of cement in Tamil Nadu and the price of cement in Kerala and Trivandrum. In Kerala and Trivandrum, the price of cement was Rs. 14(y- to Rs. 15(y- per bag in January, 1999. Now the price is Rs. 160/- to Rs. 185/- per bag. In Calicut.. ..*(Interruptions).*

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir................

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Ravi, please take your seat.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I am on a different point. The hon. Member is misleading the House. Kerala is a captive market of Indian cement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Virumbi, kindly confine to your own State.

6.00 P.M

I gave you a chance because of the fact that while Mr. Margabandu was speaking, you said that those were wrong remarks....*(Interruptions).*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: What he has accused...*(Interruptions)* What he has accused is that in Tamil Nadu alone, the price is increasing. Kindly allow *me...(Interruptions)*

SHRI VAYALAR RAVI: While defending your State, don't drag in my State.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I must first say about the prices in Tamil Nadu, and then compare it with the prices in other States. The accusation is that, in Tamil Nadu alone the prices are high. I am bound to cm pare...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I gave you time to speak about your State alone.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: This is the Council of States. We can talk about the other State also....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): No, no. Whatever Mr. Margabandu has stated regarding cement prices, you explain what the position in your State is...*(Interruptions)* ....

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, you remove that accusation ......................

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): You submit what you have to say about your *Stale...(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: He has made an accusation, but you are not allowing me to respond...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): No, no; it is not a question *of...(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I am a bit hurt....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I just told you that I would give you a chance to defend yourself on this point when you speak.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: In Tamil Nadu, in January, 1999, the price of cement per bag ranged from Rs. 135 to Rs. 150. Then, in September, 1999, it ranged from Rs. 155 to Rs. 175. The price varied depending on the quality of the cement. In Trichy, the price varied between Rs. 160 and Rs. 175; and in Madurai, it was between Rs. 160 and Rs. 180...*(Interruptions).*

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Sir, what is the topic of this discussion?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Mr. Pillai, you may not know it. It will have its reflection in Tamil Nadu. It will not have its reflection in Kerala... *(Interruptions)*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, the Minister will be very happy as the topic has derailed from oil to cement.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: He said that the prices have been increased recently. Sir, in Tamil Nadu, the price of cement in September 1996 ranged from Rs. 157 to Rs. 170; in January, 1997, it was between Rs. 140 and Rs. 170 per bag; in September, 1997, the price per bag was between Rs. 150 and Rs. 170. In April, 1998, the price of cement per bag was between Rs. 150 and Rs. 175. In September, 1998, it varied between Rs. 160 and Rs. 175 and in September, 1999, it was between 155 and Rs. 175. Therefore, it clearly shows that in our regime, the prices have not been increased steeply, as alleged by the hon. Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): That is all.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Therefore, Sir, I want to set the record right. From April to September, 1999, total cement sold in Tamil

Nadu was 38.6 lakh tones. From April to September, 1999, the total cement sold was 45.62 lakh tones. I want to put forth an argument as to how the quantity of cement sold in our State would have increased had there been an enormous increase in its price.

Then, Sir I come to diesel...*(Interruptions)* Sir, I would only like to say that the observation made by the hon. Member sis aimed at nothing but misleading the House. Ours is a corruption-free Government, and there will not be any such thing. Lastly, I would like to say that 1 would not have talked about the other States had he not made that kind of a statement.

**श्री रामजीलाल (हरियाणा)** : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। डीजल की प्राईस बढ़ाई गई है और इसके विरोध में हड़तालें हो रही है। डीजल की जो प्राईस बढ़ाई गई है, सरकार इसको बहुत लाईटली ले रही है। सरकार ने तो यह समझ रखा है कि बड़ी मामूली बात है डीजल की प्राईस बढ़ाना। महोदय, 35 परसेंट तक कीमत बढ़ाई गई है। आज तक इतिहास में इतनी प्राईस कभी नही बढ़ी है। एक बार में 10 पैसे, 15 पैसे प्रति लीटर कीमत बढ़ा करती थी और बीच में एक बार तो कीमत कम भी कर दी थी। मै डीजल की कीमत में इतनी भारी वृद्धि को देखकर हैरान हूं। सरकार कह रही है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम इंडस्ट्रीज खड़ी करेंगे, हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे लेकिन में समझता हूं कि कुछ होने वाला नही है।

अगर यह सरकार इस इलेक्शन से पहले करके देख लेती तो पता चलता। वैसे हरियाणा में कांग्रेस हारी है। दस सीटें आप लोगों ने ली है। मै आपको बता देना चाहता हूं कि आगे जब वहां असेबली का इलेक्शन होगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि डीजल की कीमत कैसे बढ़ाई जाती है। यदि आपने इसको कम नही किया, ठीक नही किया तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। अभी ट्रकों की हड़ताल हुई है। उनकी हड़ताल को लालच वगैरह देकर तोड़ा गया है। डीजल की कीमत बढ़ाने का फैसला आप इलेक्शन से पहले भी कर सकते थे। बड़ी-बड़ी पौलिसीज का फैसला केयरटकर गवर्नमेंट कर रही थी जबकि डीजल की कीमत आपने बाद में बढ़ाई। इसलिए कि लोग वोट आपको दे चुके है। मुझे बोलने का समय कम मिला है। मै आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसान जो ट्रेक्टर चला रहा है, टयूबवैल चला रहा है वह सब डीजल से चलता है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)** : वह सब प्रोसिडिग में आ गया है।

**श्री रामजीलाल** : किसान जब जेनिरेटर से काम करता है वह डीजल से चलता है। बिजली नही है तो कैसे काम चलेगा। टयूबवैल भी आजकल जेनिरेटर से चल रहा है। डीजल बगैर कोई काम नही हो रहा है। मुझे ज्यादा समय नही लेना है केवल एक-दो बातें कहानी थी। उपसभाध्यक्ष महोदय, डीजल का रेट घटाया जाए, वापस किया जाए अन्यथा बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। मै आपसे प्रार्थना करुंगा कि यह इतना गंभीर मामला है कि इससे देश में त्राहि मची हुई है। कृपया करके इस बढ़े हुए रेट को वापस लेने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Shri Bratin Sengupta, you have got just one minute.

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Sir,...*(Interruptions)...* Mr. Naidu.... *(Interruptions)...*

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, my request is that we have put a time limit. Members are speaking and are running away for catching their flights. Now, whoever is speaking now, should at least stay in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): You can say that, but I cannot say it from the Chair, Shri Bratin Sengupta.

SHRI BRATIN SENGUPTA: Sir, why should not there be an inquiry as to why the caretaker Government took a decision to raise the price of diesel on its last day in office, when the new Government was to take over and The Parliament session was to be convened in a few days? Why did this happen? There should be an inquiry to find out as to why they could not wait for a few more days.

Secondly, why did not the Petroleum Ministry approach the Finance Ministry for waiving off the customs duty on diesel? I want to ask, if the country was starving and you have to import foodgrains, in that case would you impose customs duty on that item? I want to know as to why such heavy customs and other duties have been imposed on this costly item which is imported from outside. Why was pressure not applied on the Finance Minstry? I want to know if this was due to the compulsion of rise in the price of diesel in the international market, as told by the Minister, then, what exactly that compulsion was? I want that this should be known to the House so that some tranperency is maintained.

**श्री राम नाईक** : उपसभाध्यक्ष महोदय, वैसे ही डीजल ज्वलनशील वस्तु है और जब डीजल का मूल्य बढता है तो वह हाइली इनफलेमेबल बनता है और ऐसे हाइली इनफलेमेबल विषय के बारे में यहां चर्चा हुई। पन्द्रह सदस्यों ने अपने विचार यहां रखे। मै जानता हूं कि कुछ सदस्यों को जाना था इसलिए चले गए लेकिन जिन्होंने चर्चा में भाग लिया उनको में धन्यवाद देना चाहता हूं और जो सांसद यहां बैठे है उनको भी मै धन्यवाद देना चाहता हूं।

जिस शांति से चर्चा हुई है उसी शांति से मेरी विचार भी सुने जाएंगे और उसके लिए मै प्रारम्भ में ही धन्यवाद देता हूं। शुरु में ही मै यह बात स्पष्ट कर दूं कि जो भी सुझाव यहां आए है ऐसे सुझावों पर में अपनी ओर से विचार करुंगा और उससे किस प्रकार से लाभ सबको हो सकता है इसके बारे में जरुर विचार करुंगा। मैंने एक शार्ट नोट सभी माननीय सदस्यों को दिया था। वह इसी भूमिका में दिया था कि चर्चा सार्थक हो और सरकार के पास जो तथ्य है वह सभी सदस्यों को पहले ही मालूम हों। ताकि चर्चा में उसका उपयोग भी हो सकता है और ऐसा उपयोग कुछ मान्यवर सदस्यों ने किया, उसके लिए मै धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात तो यह हुई कि 10 जुलाई, 96 में दाम बढ़ाए गए थे और उस समय पर भारतीय जनता पार्टी या अभी जो सत्ता में है, उन लोगों ने उसका विरोध किया था वगैरह-वगैरह। ऐसे पोलिटिकल गिमिक्स में मै ज्यादा जाना नही चाहता हूं लेकिन आप जरा ख्याल रखे और आपको मालूम

भी होना चाहिए कि यह जो सारी प्रकिया ऑयल पूल एकाउंट वगैरह की हो गई, बाद में जब हमारी सरकार आई और उसने निर्णय किया है, ऐसी बात नही है। यदि आप ऐसा करते है तो अच्छा है और हम करते है तो खराब है, मुझे ऐसा लगता है कि यह एक डबल स्टैडर्ड वाला मामला है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: We had opposed it when the United Front raised it on 15th July, 1996. *(Interruptions)*

SHRI RAM NAIK: That is what you are doing now when you are in the Opposition. When you were supporting the Government...*(Interruptions)...*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: At that time also we said the same thing. ...*(Interruptions)...*

SHRI RAM NAIK: Just to oppose the Government, for the sake of opposition, it is not proper. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please sit down. Dipankarji, you have already spoken. *(Interruptions)*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You are applying double standards and not us. I had asked you to go through the proceedings and know it for yourself. *(Interruptions)* That is not double standard. You go through the proceedings. *(Interruptions)*

SHRI RAM NAIK: I did not obstruct you. I did not say even a word against you when you were speaking. I think, propriety demands of you that you too should listen to me. If you want to put some questions, you can certainly do it after wards. *(Interruptions)*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: We did not apply double standards. *(Interruptions)*

SHRI RAM NAIK: You had applied double standards and I will explain to you how you had done it. *(Interruptions)* I will explain to you how you had applied double standards. और इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, एक बात तो पहले यह ख्याल में रखनी चाहिए कि ऐसे में आज देश की जो डीजल की, क्रूड ऑयल की आवश्यकता है, उसमें से लगभग सत्तर प्रतिशत क्रूड ऑयल हम आयात करते है और यह आयात वाइटल नेसेसिटी है। देश का उद्योग चलाना है, व्यापार चलाना है, यातायात चलाना है, इन सबके लिए हम आयात करते है और यह आयात ऐसे ही चलता रहे तो देश के लिए निश्चित तौर पर वह लाभदायक नही रहेगा। इसलिए एक लांग टर्म मेजर के नाते जिसका उल्लेख दो-तीन माननीय सदस्यों ने किया है कि अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाना एक बहुत आवश्यक बात है और आने वाले दिनों में हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि जहां-जहां एक्सप्लोरेशन किया गया है, थोड़ी जानकारी मिली है, वहां से जल्दी से जल्दी हम क्रूड ऑयल साइंटिफिक पद्धति से कैसे निकाल सकते है, इसके बारे में हम एक वृहत योजना बनाएंगे।

दूसरी एक बात जिसका उल्लेख कुछ माननीय सदस्यों ने किया है कि केरोसीन, केरोसीन की मिलावट, केरोसीन के दाम, डीजल में जो मिलावट होती है आदि मै यह चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि सदन इस काम में भी सरकार को सहयोग देगा और वह यह है कि यह जो केरोसीन की मिलावट होती है, उसके विरोध में शब्द का उपयोग किया है इसलिए मै कह रहा हूं हम धर्मयुद्ध छेड़ना चाहते है। अब धर्मयुद्ध शब्द अच्छा नही लगता इसलिए जिहाद छेड़ना चाहते है और इस काम में सारा सदन मुझे सहयोग देगा, ऐसी मै आशा रखता हूं। अब आखिर ऑयल पूल का मामला क्या है? और हम विदेश से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते है और इम्पोर्ट करने चाहते है, उसमें एक समानता रहनी चाहिए पैरिटी रहनी चाहिए इस प्रकार की बात निहित है जिसका उल्लेख कई सदस्यों ने किया है। ऑयल प्राइस पैरिटी का सवाल क्यों उठा? वह इसलिए उठा कि ऑयल पूल एकाउन्ट में 18,200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। यह घाटा कोई एक दिन में नही हुआ। इसके बारे में क्या किया जाए इस पर उस समय सदन और सरकार ने विचार किया था। कांग्रेस की ओर से पहली समिति 18 जनवरी, 1995 में बनी थी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल इंडस्ट्री के तौर पर यह समिति बनाई गई थी। कांग्रेस सरकार ने भी उस समय उसके बारे में विचार किया था। अब कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों ने भी यहां विरोध किया है। कांग्रेस के बाद जब संयुक्त मोर्चा की सरकार आई तो उसके सामने यह समस्या और गंभीर बनी। इसलिए सितम्बर 94 में उसने फैसला किया कि डीजल के बारे में जो आयात की कीमत है और देश की जो कीमत है उसमें समानता रहनी चाहिए और इस बारे में उन्होंने निर्णय लिया। उसके बाद हमारी सरकार आई तो हम उस निर्णय को कार्यान्वित किया। मुझे ऐसा लगता है कि यह विषय राजनीतिक चर्चा से परे होना चाहिए क्योकि इसमें कान्सेसस बनता आया है। कांग्रेस सरकार ने इसको बनाया, जनता सरकार या संयुक्त मोर्चा सरकार ने निर्णय लिया और अब हमारी सरकार आई है तो हम उसको कार्यन्वित कर रहे है। इसमें एक कंटीन्युटी जो सरकार में होनी चाहिए मुझे लगता है वह इसमें है। लेकिन आज लोग इस बात को लेकर आंदोलन करना चाहते है। कांग्रेस के एक माननीय प्रवक्ता का मेरे पास उद्धरण है और मै उसको पढकर सुनाना चाहता हूं। It has appeared in the Times of India on the 24th October, 1999. वे कांग्रेस की दृष्टि से बड़े माननीय विचारक है, आर्थिक विषयों के व्यक्ति है। मै उसको कोट कर रहा हूं: "There is no economic or social case for a diesel subsidy. The only social case for subsidy is kerosene. Every time when the international price of diesel goes down, they should be decreased here and when every time prices go up, our prices should increase. It is essential to link diesel prices to the international market. The decision to do away with subsidy was taken by the United Front Government in late 1997, based on the report of a Committee constituted by the Congress..."

यह आखिर का वाक्य थोड़ा अधिक महत्व का है।

"...It is the height of intellectual hypocrisy to oppose the increase in prices."

अब ऐसा कांग्रेस के माननीय सदस्य कहते है और आप इसमें विरोध करते है।

SHRI VAYALAR RAVI: It is only one Congress leader's statement. There are many other leaders in the Congress party...*(Interruptions)*...They

don't agree with that statement...*(Interruptions)...*Why have you quoted that statement?... *(Interruptions)...*

SHRI RAM NAIK: I know the Congress leaders speak in different voices everywhere...*(Interruptions)...*That I know...*(Interruptions)...*

SHRI VAYALAR RAVI: You are quoting conveniently a junior Congressman. You say what the Congress President has said... *(Interruptions)...!* can quote Mr. Advani's statement against Mr. Vajpayee's statement. ..*(Interruptions)..* .Do you want me to do that?...*(Interruptions)...*,No, no, that is not the way...*(Interruptions)...*

SHRI RAM NAIK: I am quoting this quotation...*(Interruptions)...*You want me to name that person?...*(Interruptions)...* SHRI VAYALAR RAVI: *Yes...(Interruptions)...*

SHRI RAM NAIK: Okay...*(Interruptions)...*His name is, Mr. Jayaram Ramesh, Secretary, Economic Affairs Department of the Congress. ..*(Interruptions)...*

**श्री ललितभाई मेहता (गुजरात)** : क्या वे कांग्रेस के प्रवक्ता नही है? ...(**व्यवधान**)...

SHRI VAYALAR RAVI: I thought you are quoting the Congress President...*(Interruptions)...*Or, the Leader of the Opposition, who is sitting here...*(Interruptions)...*You are quoting somebody else...*(Interruptions)...*Sir, Congress is a big party; not like your party...*(Interruptions)...*

**श्री राम नाईक**: देखिए। इसमें ऐसे गुस्सा करने का क्या फायदा है? ...(**व्यवधान**)...

SHRI VAYALAR RAVI: Why can't you quote *me...(Interruptions)...!* can give some statement...*(Interruptions)...*You quote *me...(Interruptions)...*

SHRI VENKAIAH NAIDU: You are not Mr. Jayaram Ramesh...*(Interruptions)...*That is the problem...*(Interruptions)...*

SHRI VAYALAR RAVI: I am not convenient to you...*(Interruptions)...*1 am not convenient to *you...(Interruptions)...*

SHRI VENKAIAH NAIDU: Mr. Jayaram Ramesh is an intellectual... *(Interruptions)...* He has got experience in a particular field... *(Interruptions)...*

SHRI RAM NAIK: I never knew that you are such an economist or spokesperson on economic affairs. But, since you have said now, in future, I will try to quote your quotation and use it against you...*(Interruptions)...*

**उपसभाध्यक्ष जी ,बात** तो केवल इतनी ही है कि राजनीति ज्यादा लांघने की आवश्यकता नही है और जो नीतिगत निर्णय पहले की सरकार ने लिए है और जैसा मैंने कहा कंटीन्यूटी रही है तो उस कंटीन्यूटी के बारे में सोचना चाहिए। सितम्बर, 1997 से अक्तूबर 1999 तक हमने क्या किया? जो निर्णय हुआ था उस निर्णय के अनुसार कुल मिलाकर नौ बार कीमतों में परिवर्तन किया गया। इन परिवर्तनों में

जो पांच अक्तूबर को परिवर्तन किया गया उसे पकड़कर उसमें छह बार कीमतें कम की गई और तीन बार कीमतें बढ़ाई गई। जब कीमतें घटानी थी तो घटाई गई और जब बढ़ानी थी तो बढ़ाई गई लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्किट में डीजल प्राइजस में एक नई ऊंचावट, नई इन्क्रिज फरवरी, 1999 से आनी शुरु हुई और फरवरी, 1999 तक, जो मैंने नोट दिया है उसमें, और सभी जानते है कि क्रूड ऑयल का प्राइस 3,210 रुपये पर टन था और यह सितम्बर, में बढकर 7,020 हो गया, जोकि 119 प्रतिशत बढत थी। अब जैसे क्रूड ऑयल में प्राइस इन्क्रिज हो गया वैसे ही डीजल में 94 प्रतिशत प्राइस इन्क्रिज हो गया। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बीच में आपने क्या किया? अप्रैल में हमने प्राइसस भी रिवाइज किए जो कि तुम आसानी से भूल गए। और फिर सवाल आ गया कि अप्रैल के बाद क्या है। आपने क्यों नही बढ़ाया? कुछ माननीय सदस्यों पर चुनाव का बोझ अभी भी इतना हावी है कि केवल चुनाव को छोड़कर इस समय देश में और क्या हुआ इसे भूल गए ऐसा हमें लगा। यदि हार गए तो उन्हें मानना चाहिए कि हार गए क्योकि पोलिटिकल डिफीट तो चलती रहती है, उसमें क्या है, परंतु उसका पोलिटिकली एनालिसस करना कभी-कभी कांग्रेस वालों को सही ढ़ंग से नही आता है तो इसमें हमारा दोष नही है। लेकिन यह समझना चाहिए कि अप्रैल 1999 से 5 अक्तूबर, 1999 तक देश में चुनाव नही हुए। देश में कारगिल के विषय को लेकर पाकिस्तान के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। महोदय, मई, जून, जुलाई, तक देअर इज ए वार,शुड नाट फोरगेट इट एण्ड वेनएवर देअर इज ए वार ...(**व्यवधान**)... जब देश लड़ाई करता है तो ...(**व्यवधान**)...

SHRI VAYALAR RAVI: In 1996-97, the total payment was 10 million dollars. Now, this year, it has gone up to 10.5 million dollars. ...*(Interruptions)...*

SHRI RAM NAIK: I have not yielded. ...*(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTAN BISI): No, no, please; he is not yielding. ...*(Interruptions)...*

SHRI RAM NAIK: A senior Member should have the courtesy to ask me to yield. Now, tell me what you want to say.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I want to ask the honourable Minister, apart from the Kargil war, according to the reports available here, and as has been pointed out by Shri Dipankar Mukherjee, in 1996-97, the import bill was to the tune of 10 million dollars. This year, it may go up to 10.5 million dollars. In Mumbai, in 1996-97, the price of one litre of diesel was less than Rs. 11.00. When you were paying 10 million dollars for the import of oil, the price was less than Rs. 11.00. Now, in Mumbai, it has gone up to Rs. 16.00 per litre. ...*(Interruptions)...*

SHRI RAM NAIK: That means you are not aware of the value of the dollar vis-as-vis the rupee some four years back and now. ...*(Interruptions)...*You should be aware that the dollar and the rupee are not of the same value *(Interruptions)...*, उपसभाध्यक्ष जी, मै यह कह रहा था कि देश कारगिल के विषय पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा था और जब लड़ाई होती है तब देश में सबसे

बड़ी आवश्यकता इस बात की होती है कीमतों को स्थिर रखना। और कीमतों को स्थिर रखने के अलग-अलग तरीके हमने अपनाए तथा मुझे इस बात की खुशी है कि आज तक चार बार लड़ाई हो चुकी है तथा हर लड़ाई में कीमतें बढती ही जाती थी और लोग चिंतां करते थे कितु यह पहली लड़ाई है जिसमें कीमतें स्थिर रही और इसलिए मै इस सदन तथा देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सदन के माध्यम से मै देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं व्यापार और उद्योग जगत को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने जब देश लड़ाई लड़ रहा था, उस समय कीमतें स्थिर रखी। लेकिन मै आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस लड़ाई को भूल गए है? यहां पर एक भी मान्यवर सदस्य ने इस लड़ाई का उल्लेख नही किया। मुझे खेद है कि आप इतने गंभीर विषय पर भी चुनावी राजनीति करना चाहते है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: When the Minister is charging that...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTAN BISI): No, he is not charging.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, whatever I had spoken, was all technical in nature.

SHRI RAM NAIK: I am not yielding, now. *(Interruptions)*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I had said that two years back its price was $163 per barrel. You answer on this point. But, Sir, he is politicizing the reply.

SHRI RAM NAIK: I have not used any word of politics.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please take your seat. Let him complete his reply first.

SHRI RAM NAIK: If you want, you can ask questions after I complete my reply, वह खड़े होकर बात कर रहे है। मैंने जब यील्ड नही किया तो वह क्यों अपनी बात कहते जा रहे है?

**श्री एम. वैकैया नायडु** : वे खुद ही सवाल कर सकते है और खुद ही जवाब दे सकते है।

**श्री राम नाइक** : दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि इस समय इंटरनेशनल मार्किट में क्रूड आयल के प्राइस बहुत बढ़े हुए है और जब वोनाटाइल मर्किट होता है, जब वह बढता है तो उसकी ओर ध्यान देने की जरुरत होती है। यह भी एक कारण है कि हमने उस समय पर तुरन्त कार्यवाही नही की। अब आयल पूल एकाउन्ट, हमारे मित्र दीपांकर मुखर्जी ने कुछ बातें कही है। मैंने तो उनको 20 अक्तूबर को नोट भेजा था। उन्होंने अगर मुझे इस बारे में पहले भेजा होता, जब वह भाषण देने के लिए खड़े हुए उस समय पर वह भेजा। अगर वे उसे थोड़ा पहले भेज देते तो मै आपको टाइम पर जवाब भेज देता। ...(**व्यवधान**)... मै आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि उन्होंने जो जो मुद्दे यहां उठाए है या लिखकर भेजे है उन पर विचार करुंगा और जरूर उनका उत्तर उनको भेज दूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): That is all.

SHRI RAM NAIK: No, Sir. This is so far as the observation he has made is concerned. आयल पूल एकाउंट के बारे में मै यह कहना चाहता हूं कि 30 जून, 1997 को जब यू.एफ.गवर्नमेंट थी उस समय घाटा 18200 का था। अब जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई तो 31 मार्च 1998 को यह घाटा 14156 करोड़ रुपए का रह गया और एक साल बाद 31 मार्च, 1999 को यह घाटा 3408 करोड़ रुपया रह गया। एक सब्सटेशियल घाटा हम लोगों ने एक साल में कम किया, लगभग 11 करोड़ रुपए का घाटा हम लोगों ने कम किया। लेकिन अब फिर कीमतें बढने लगी तो 5200 आयल पूल एकाउंट का डिफिसेट हो गया तो हमने सोचा कि अब कीमतें बढ़ानी चाहिए। न बढने तो आयल पूल एकाउंट 31 मार्च, 1999 तक, आज के जो दाम है, अगर वे इसी प्रकार रहते तो यह घाटा 10 हजार हो जाता। लेकिन कुछ स्थिति सुधर जाएगी ऐसा भी अंदाजा आ रहा था। अगर ऐसा होता है तो हमारा अंदाजा ऐसा था कि 31 मार्च, 1999 को 3900 तक यह घाटा कम हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास इस समय कोई दूसरा चारा नही था ताकि हम इम्पोर्ट कम कर सकें। अब अगर हम इम्पोर्ट कम करते है तो उसका दुष्परिणाम देश के उद्योग, व्यापार आदि सारे काम काज पर हो जाता। इसलिए इसको इम्पोर्ट करना आवश्यक था। जब इम्पोर्ट करना आवश्यक था तो इसमें ज्यादा टाइम लग गया। फिर इसकी कीमतों को बढ़ाने में हमें कोई खुशी नही हुई। जब लोगों से वोट लेकर और उनकी सहायता से हम यहां जीतकर आए है तो हम लोगों को नाराज क्यों करेंगे? हमने जो ऐसा कदम उठाया इसका एक ही कारण था कि हमारे सामने इसके सिवा और कोई दूसरा चारा नही था। एक चारा यह जरुर था कि हम मार्किट से आयल पूल एकाउंट में जो डिफिसेट है उसको पूरा करने के लिए पैसा लें। लेकिन अगर हम मार्किट से पैसा लेते तो उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता।

THE VICE-CHAIRMAN [SHRI SANATAN BISI]: Mr, Mukherjee, do you want to seek any clarification?....*(Interruptions)...* The Minister has already stated... *(Interruptions)....*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The Miniser has not replied to that point. He has not touched on it. The first point that I referred to was with regard to a newspaper report of 6th October wherein Mr. Ramachandran, Executive director, Oil Co-ordination Committee stated, "A decision has been taken by the OCC. The Cabinet has nothing to do with that." This is what Mr. Ramachandaran has said at a press conference...*(Interrupions)...* Mr. Ramachandran, Executive Director, Oil Co-ordination Committee, had announced this price rise. This has been reported in the newspaper on 6th October. "This is a decision taken by the OCC." The Cabinet has nothing to do with this. This has been reported in "The Economic Times" dt. 6th October. If you deny this, please check up, whosoever has given this statement, because it is very important point. This is my first point.

My second point is if his hands are tied, it is because of the basic price and other duties. When the market was soft, the Finance Minister has put Re. las duty or cess; whatever it is. When the market has become hard, why should the consumer pay it? You are not going to reduce. That is why I reqest you to tell your Finance Minister about this. When the market was soft, the

international price of diesel was $83 per metric tonne and then you put a duty. When the international price touched $162 per metric tonne, you put a proportionate burden on the consumers and then you also claim that you have reduced it. The point is: why was this duty imposed when the market was sfot? When the market is not soft, you say it is hard. The Government has to take away, at least, that Re. 1 duty Do you think the market is soft or hard! If it is hard, then that duty cannot be there. If you cannot reply, the Leader of the House is there, let him explain. It is the Governemnt, it is a collective entity. The consumer has to pay everything. My point is if, the market was not soft, how could that Re. 1 cess still continue? That cess must be withdrawn, if the Government is not wthdrawing it, let them explain the reasons.

SHRI RAM NAIK: Mr. Vice-Chairman, Sir I have already replied to it.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: He has not replied. That is the point.

THE VICE-CHAIRMAN [SHRI SANATAN BISI]: During the Short Duration Discussion, whatever norms are there, we have to follow that. You raise certain question. The Minister replies to them. Finally, if you don't agree... *(interruptions)..*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I would like to know whether the market is soft or hard.

THE VICE-CHAIRMAN [SHRI SANATAN BISI] : During the discussion, we cannot do anything.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : If the market is soft, you pay it.

SHRI RAM NAIK : A* I explained earlier, in September, 1997, the Cabinet has applied its mind regarding the revision of price and maintaining parity on that. The Cabinet worked out and approved a methodology as to how to do it and how not to do it. Then the Committee was authorized to work it out accordingly. So far as the Sth October issue is concerned, the Cabinet took all these things into account. As per the earlier practice, the Cabinet decided that the price should be increased.

This is as simple as that. Now, why that officer has said anything, I will have to find out. This is as simple as that. The Cabinet applied its mind and decided that the formula which is in force should apply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI) : Now, we will take up the *'sou motu'* statement by the External Affairs Minister.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I have two statement to make. If you permit me, I will read out both the statements.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI) : The other has not been circulated.

SHRI JASWANT SINGH : It can be circulated straightway.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : In the meantime he can go on reading the first statement.

## STATEMENT BY MINISTER

### I. Signing of three agreements including the extradition treaty between India and UAE
### II. Recent visit of United States Secretary of Energy to India

THE MINISER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH) : Sir the U.A.E. Minister for Justice, Islamic Affairs and Awqaf, H.E. Mr. Mohammed Bin Nakhira al Dhaheri, accompained by an official delegation, visited India on October 25-26, 1999.

During the visit, an Extradition Treaty, an Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters and an Agreement on Juridical and Judicial Cooperation in Civil and Commercial matters between India and the UAE, were signed.

The extradtion Treaty would .provide a legal framework for seeking the extradition of fugitive criminals including those involved in terrorism and economic offences from either country. Under the Treaty, extradition would be possible irrespective of whether the crime was committed before or after the entry into force of this Treaty.

The Agreement on Juridical and Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters aims to facilitate the widest measure of legal assistance in pursing such cases. As a result of this Agreement, it will be possible to serve summons and other judicial documents issued by the courts of one country in the territory of the other. The judicial authority of one country could also, at the request of the other, take evidence. Further, the courts of one country would also be able to execute decrees and arbitration awards passed in the territory of the other.

The Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters aims to strengthen the cooperation between the two countries in the completion of investigation and prosecution in respect of all crimes, including those related to terrorism. It would provide the basis for seeking assistance for tracing, restraint, forfeiture or confiscation of the proceeds and instruments of crime. The Agreement will also facilitate the widest measure of mutual assitance in